Useful For Prelims

Date: 05 January 2026

अंतरिक्ष में न्यूक्लियर इंजन की पहली परीक्षा

जिस सपने को विज्ञान-कथा में दशकों तक देखा गया, वह अब हकीकत बनने की कगार पर है। नासा और अमेरिकी रक्षा एजेंसी डीएआरपीए अंतरिक्ष में पहली बार न्यूक्लियर ताकत से चलने वाले रॉकेट इंजन का परीक्षण करेंगी। ड्राको प्रोग्राम के तहत यह रॉकेट मंगल ग्रह की यात्रा को न सिर्फ तेज बना सकता है, बल्कि यात्रियों के लिए इसे ज्यादा सुरक्षित और अधिक सामान ले जानी वाली अंतरिक्ष यात्रा को बना सकता है।

मंगल ग्रह तक जल्दी पहुंच

अभी मंगल तक जाने में 7–9 महीने लगते हैं। लेकिन ड्राको मिशन के तहत समय लगभग 25% कम हो सकता है। इसके जरिए भारी सामाना को भी ले जाया सकता है।

50 साल से ज्यादा समय बाद होगा फिर से परीक्षण

पहले भी 1960–70 के दशक में नेरवा नाम का प्रोजेक्ट चला था। लेकिन तब पैसे की कमी से मिशन नहीं हुआ। अब तकनीक बेहतर है और ध्यान मंगल पर है।

इस तरह होगा परीक्षण

परीक्षण इस साल की शुरुआत में हो सकता है। लॉन्च के समय न्यूक्लियर रिएक्टर बंद रहेगा जब रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में पहुंच जाएगा तब रिएक्टर को चालू किया जाएगा।

इस तरह करेगा काम

1. रॉकेट में आग जलाकर गैस छोड़ी जाती है, लेकिन इसमें यूरेनियम का इस्तेमाल होगा। यूरेनियम आग नहीं जलाता, बल्कि भट्ठी की तरह गर्मी पैदा करता है। गर्मी से लिक्विड हाइड्रोजन को इतना गर्म किया जाता है कि वह फैलती है, रॉकेट को आगे की तरफ धक्का देती है।

2. आज के रॉकेट का माइलेज सीमित है। विज्ञान की भाषा में इसे स्पेसिफिक इम्पल्स कहते हैं। रॉकेट 450 सेकंड की क्षमता रखते हैं। यह नया इंजन 900 सेकंड की क्षमता रखता है। यह उतने ही ईंधन में आज के रॉकेट से दो गुना ज्यादा दूरी तय कर सकता है।

3. वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि धरती पर इसका रेडिएशन भी नहीं फैलेगा। किसी को नुकसान नहीं होगा। जब रॉकेट धरती से उड़ान भरेगा, तब इसका परमाणु रिएक्टर पूरी तरह बंद रहेगा। जब रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा, तभी इसे चालू किया जाएगा।

4. वैज्ञानिकों ने कहा कि इस मिशन का मकसद सिर्फ यह जांच करना है कि क्या यह परमाणु इंजन वाकई अंतरिक्ष के माहौल में सही तरीके से काम करता है या नहीं।

Hindustann Page No-16

अंतरिक्ष विज्ञानियों ने खोजा सौरमंडल का सबसे भारी बौना ग्रह

अंतरिक्ष विज्ञानियों ने 2005 में आज ही सौरमंडल के सबसे भारी और दूसरे सबसे विशाल बौने ग्रह एरिस की खोज की थी। इसे एमई ब्राउन, सीए ट्रुजिलो और डीएल रिबिनोवित्ज की टीम ने खोजा। ग्रह का द्रव्यमान प्लूटो से 27 प्रतिशत अधिक है जबकि आकार उससे थोड़ा छोटा है।

पटौदी की अगुआई में टीम ने विदेशी धरती पर हासिल की पहली जीत

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी का जन्म 1941 में आज ही के दिन भोपाल में हुआ था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण के कुछ समय बाद ही उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई। इस कमजोरी को धता बताते हुए नए उत्साह के साथ मैदान पर उतरे। 1962 में भारतीय टेस्ट टीम की कमान संभाली और सबसे कम उम्र के कप्तान बने। पटौदी के नेतृत्व में 1967 में पहली बार भारतीय टीम ने विदेशी धरती पर जीत दर्ज की। उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा लेकिन सफल नहीं हुए। 22 सितंबर, 2011 को उनका निधन हो गया।

Dainik Jagaran Page No-14

अमेरिका ने 1989 में पनामा पर हमला कर नोरीगा को पकड़ा था | **विश्लेषण** | रुबियो ने कहा, वेनेजुएला पर आगे किसी कार्रवाई की संभावना नहीं

वेनेजुएला से पहले भी कई देशों में सैन्य कार्रवाई कर चुका है अमेरिका

फिलाडेल्फिया, 4 जनवरी (एजंसी)।

अमेरिका ने छुट्टियों के दौरान आधी रात को एक लैटिन अमेरिकी देश के भीतर अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य इस बहाने से उस देश के नेता को पकड़ना था कि वह अमेरिकी अदालतों में मादक पदार्थों के आरोपों में वांछित है।

अमेरिका के इस अभियान की तारीख 20 दिसंबर 1989 थी, देश पनामा था और वांछित व्यक्ति जनरल मैनुअल नोरीगा थे। अमेरिका में तीन जनवरी, 2026 को जागने वाले कई लोगों को शायद 'डेजा वू' (पहले भी ऐसा हो चुका है) का अहसास हुआ होगा। हालांकि, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी अमेरिकी विदेश नीति के एक पुराने युग की याद दिलाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि एक रात्रिकालीन अभियान में अमेरिकी सैनिकों ने दंपति को वेनेजुएला की राजधानी काराकस से पकड़ लिया और उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यह घटना ट्रंप द्वारा असाधारण सैन्य अभियान के रूप में वर्णित घटना के बाद हुई, जिसमें अमेरिका के वायु, थल और नौसैनिक बलों को शामिल किया गया था।

मादुरो और उनकी पत्नी को मादक पदार्थों से संबंधित आरोपों का सामना करने के लिए न्यूयार्क ले जाया गया। मादुरो पर 2020 में आतंकवाद-मादक पदार्थों से संबंधित अभियान का नेतृत्व करने के आरोप में अभियोग लगाया गया था, जबकि उनकी पत्नी को चार अन्य नामित वेनेजुएलावासियों के साथ एक नए अभियोग में शामिल किया गया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि उन्हें वेनेजुएला में आगे किसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं है। अमेरिका की यह कार्रवाई तेल समृद्ध वेनेजुएला पर महीनों से बढ़ाए जा रहे दबाव की परिणति है।

ट्रंप ने कहा कि उन्हें अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी से डर नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, अमेरिका-लैटिन अमेरिकी संबंधों के विशेषज्ञ के रूप में, मैं वेनेजुएला में अमेरिकी अभियान को हाल के अतीत से एक स्पष्ट बदलाव के रूप में देखता हूं। यह उस राजनयिक दृष्टिकोण को त्याग देता है जो दशकों से अंतर-अमेरिकी संबंधों की पहचान रहा है।

दरअसल, 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के पतन के बाद से ही इस क्षेत्र में संभावित प्रभाव क्षेत्रों पर वैचारिक पकड़ कमजोर हो गई।

परंपरा से हटकर

ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती कार्यों में से एक, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर 'अमेरिका की खाड़ी' करना, इस नई नीतिगत दिशा के अनुरूप है। लेकिन कई मायनों में, ट्रंप प्रशासन द्वारा मादुरो को हटाने के लिए चलाए गए अभियान का कोई पूर्व उदाहरण नहीं है। वाशिंगटन की पिछली सभी प्रत्यक्ष कार्रवाइयां मध्य अमेरिका या कैरेबियाई क्षेत्र के छोटे, निकटवर्ती देशों में थीं। अमेरिका ने मैक्सिको में अक्सर हस्तक्षेप किया लेकिन उसने कभी भी सीधे तौर पर उसके नेतृत्व को नहीं हटाया या पूरे देश पर कब्जा नहीं किया।

दक्षिण अमेरिका में हस्तक्षेप अप्रत्यक्ष रूप से किए जाते थे

लिंडन जानसन के पास ब्राजील में 1964 के तख्तापलट के असफल होने की स्थिति में एक वैकल्पिक योजना थी (हालांकि तख्तापलट सफल रहा)। रिचर्ड निक्सन ने 1970 से चिली में समाजवादी सरकार को कमजोर किया, लेकिन उन्होंने 1973 में राष्ट्रपति सल्वाडोर अलेंडे के खिलाफ तख्तापलट की साजिश नहीं रची। एक समय अमेरिकी अधिकारियों का मानना था कि दक्षिण अमेरिकी देश बहुत दूर, बहुत बड़े और बहुत स्वतंत्र हैं, इसलिए उन्हें प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नहीं होती। जाहिर है, ट्रंप के अधिकारियों ने इस ऐतिहासिक अंतर को नजरअंदाज कर दिया।

Jansatta Page No-18

अमेरिका के लिए राह आसान नहीं; लोग सड़कों पर, रूस-चीन समेत कई देशों ने की हमले की निंदा

वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति बनीं डेल्सी रोड्रिगेज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जनवरी।

अमेरिका के हमले के बाद डेल्सी रोड्रिगेज को वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। अमेरिका द्वारा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के पकड़े जाने के बाद वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट आफ जस्टिस ने शनिवार देर रात वहां की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति की जिम्मेदारी सौंपने का आदेश दिया।

कोर्ट की मजिस्ट्रेट तानिया डीमेलियो ने नैशनल रेडियो और टेलीविजन पर अदालत का फैसला पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया, 'यह आदेश दिया जाता है कि रिपब्लिक की एग्जीक्यूटिव उपराष्ट्रपति, डेल्सी एलोइना रोड्रिगेज गोमेज, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्रपति के पद से जुड़ी सभी शक्ति, कार्य और विभागों को अपनाएं और उनका इस्तेमाल करें।'

आदेश में यह भी कहा गया कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर रोड्रिगेज की भूमिका तुरंत शुरू की जानी चाहिए। हम वेनेजुएला के लोगों और इलाके के खिलाफ अमेरिका द्वारा किए गए बहुत गंभीर सैन्य हमले, साथ ही मादुरो और उनकी पत्नी की अपहरन को खारिज करते हैं। देखा जाए तो मादुरो ने 2.9 करोड़ की आबादी वाले राष्ट्र में असफल तख्तापलट के एक प्रयास, सैन्य विद्रोहों, विरोध प्रदर्शनों और आर्थिक प्रतिबंधों का सामना किया था।

सच तो यह है कि वेनेजुएला पर हुए हमले को लेकर लोगों में आक्रोश है। न्यूयार्क में इसका विरोध किया गया है। इसके साथ ही कई देशों ने इस घटना की निंदा की है। वहीं देश की बागडोर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है कि वेनेजुएला पर अमेरिका नियंत्रण कर लेगा और ऐसा संभवतः मादुरो के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक के साथ मिलकर किया जाए। का आदेश दिया। ट्रंप ने रोड्रिगेज के बारे में कहा, 'वह वेनेजुएला को फिर से महान बनाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक समझती हैं, वह करने को तैयार हैं।' ट्रंप ने कहा कि विपक्षी नेता एवं पिछले साल नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मारिया कोरिना मचाडो के पास देश चलाने के लिए आवश्यक समर्थन नहीं है। इस बीच वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन हुए। काराकस में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान, मेयर कारमेन मादुरो को छोड़ने की मांग कर रही भीड़ में शामिल हुईं। भीड़ नारे लगा रही थी, 'मादुरो, टिके रहो, जनता उठ खड़ी हुई है। अगर आप हमें सुन सकते हो, तो जान लो कि हम यहां हैं!

राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के विरोध में नारे लगाते लोग।

कौन हैं डेल्सी रोड्रिगेज

वेनेजुएला के संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति की स्थिति में एक महीने के भीतर नए चुनाव कराए जाने चाहिए। रोड्रिगेज ब्रिटेन और फ्रांस में पढ़ी हैं तथा वह एक वकील हैं। उनके भाई जार्ज रोड्रिगेज मादुरो-नियंत्रित नैशनल असेंबली के प्रमुख हैं। उनके पिता समाजवादी नेता थे जिनकी 1970 के दशक में पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी। मादुरो के करीबी लोगों में से कई पर अमेरिका में आपराधिक आरोप लगाए गए हैं, लेकिन रोड्रिगेज भाई-बहन के साथ ऐसा नहीं हुआ। डेल्सी रोड्रीगेज के तेल उद्योग और वाल स्ट्रीट से जुड़े रिपब्लिकन नेताओं के साथ मजबूत संबंध हैं। वाल स्ट्रीट अमेरिका में वित्त और शेयर बाजार का केंद्र है।

'मादुरो व उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करें'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जनवरी।

चीन ने रविवार को अमेरिका से वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने तथा संवाद व बातचीत के माध्यम से मुद्दों को हल करने का आह्वान किया। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, अमेरिका द्वारा अपदस्थ किए गए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को जबरन हिरासत में लेकर देश से बाहर ले जाने पर चीन गहरी चिंता व्यक्त करता है।

बयान में कहा गया कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों तथा सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है। चीन अमेरिका से अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें तुरंत रिहा करने, वेनेजुएला सरकार को गिराने का प्रयास रोकने तथा संवाद एवं बातचीत के माध्यम से मुद्दों को हल करने का आह्वान करता है।

इससे पहले शनिवार को विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हवाई हमलों और मादुरो तथा उनकी पत्नी की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे एक वर्चस्ववादी कृत्य बताया जो अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर रूप से उल्लंघन करता है। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी हवाई हमलों और मादुरो तथा उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि वह एक संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ अमेरिका द्वारा बल का खुलेआम इस्तेमाल किए जाने और उसके राष्ट्रपति के खिलाफ कार्रवाई से बेहद स्तब्ध है।

'अमेरिकी कार्रवाई खतरनाक मिसाल'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जनवरी।

एंतोनियो गुतारेस

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने वेनेजुएला और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई पर चिंता जताते हुए कहा कि ये घटनाक्रम 'खतरनाक मिसाल' कायम करते हैं।

महासचिव के प्रवक्ता की ओर से शनिवार को जारी बयान में कहा गया कि गुतारेस 'वेनेजुएला में हाल में हुए उस घटनाक्रम से अत्यंत चिंतित हैं जिसके तहत अमेरिका ने आज देश में सैन्य कार्रवाई की और क्षेत्र के लिए इसके संभावित रूप से चिंताजनक निहितार्थ हो सकते हैं।' गुतारेस ने कहा कि वेनेजुएला की स्थिति से अलग, 'ये घटनाक्रम एक खतरनाक मिसाल कायम करते हैं।' उन्होंने कहा कि उन्हें 'इस बात की गहरी चिंता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान नहीं किया गया।'

मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयार्क के संघीय अधिकारियों ने मादक पदार्थों से संबंधित आतंकवाद की साजिश और अमेरिका के खिलाफ विनाशकारी उपकरण रखने की साजिश के आरोपों में अभियोग लगाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार तड़के 'ट्रुथ सोशल' पर घोषणा की थी कि अमेरिका ने वेनेजुएला और मादुरो के खिलाफ 'बड़े पैमाने' पर 'सफलतापूर्वक' हमला किया और 'मादुरो को उनकी पत्नी के साथ पकड़ लिया गया है एवं उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है।

तेल क्षेत्र पर अमेरिकी नियंत्रण से

भारत को वेनेजुएला से मिल सकता है एक अरब डालर का बकाया

नई दिल्ली, 4 जनवरी (भाषा)।

विश्लेषकों और उद्योग सूत्रों के अनुसार, वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर अमेरिकी नियंत्रण अथवा उसके पुनर्गठन से भारत को प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। विश्लेषकों ने बताया कि इस घटनाक्रम के चलते काफी समय से लंबित भारत के लगभग एक अरब अमेरिकी डालर के बकाये की वसूली हो सकती है और प्रतिबंधों से प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय संस्थाओं द्वारा संचालित तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल का उत्पादन भी बढ़ सकता है। उल्लेखनीय है कि भारत एक समय वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल का प्रमुख आयातक था और अपने चरम काल में प्रतिदिन चार लाख बैरल से अधिक का आयात करता था। हालांकि, 2020 में अमेरिकी प्रतिबंधों और अनुपालन जोखिमों के कारण यह आयात बाधित हो गया था।

भारत की प्रमुख विदेश तेल अन्वेषण एवं उत्पादन कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) पूर्वी वेनेजुएला के ह्यसैन क्रिस्टोबलह्ण तेल क्षेत्र का संयुक्त संचालन करती है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण आवश्यक तकनीक, उपकरण और सेवाओं तक पहुंच बाधित होने से वहां उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और व्यावसायिक रूप से उपयोगी भंडार लगभग फंस गए। वेनेजुएला सरकार ने इस परियोजना में ओवीएल की 40 फीसद हिस्सेदारी पर 2014 तक देय 53.6 करोड़ अमेरिकी डालर का लाभांश अभी तक नहीं चुकाया है। इसके बाद की अवधि के लिए भी लगभग समान राशि बकाया है, किंतु ऑडिट की अनुमति न मिलने के कारण इन दावों का निपटान लंबित है। विश्लेषकों के अनुसार, यदि अमेरिका वहां के तेल भंडार को अपनी निगरानी में लेता है, तो प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। इसके बाद ओवीएल गुजरात और अन्य क्षेत्रों से रिग एवं अन्य उपकरण भेजकर उत्पादन में वृद्धि कर सकती है। इस समय यह उत्पादन घटकर मात्र 5,000 से 10,000 बैरल प्रतिदिन रह गया है। अधिकारियों का अनुमान है कि यदि उन्नत उपकरण और अतिरिक्त तेल कुओं का उपयोग किया जाए, तो उत्पादन बढ़कर 80,000 से 1,00,000 बैरल प्रतिदिन हो सकता है। इसके लिए आवश्यक रिग ओएनजीसी के पास पहले से उपलब्ध हैं।

अमेरिकी नियंत्रण का अर्थ यह भी है कि वैश्विक बाजार में वेनेजुएला से निर्यात शीघ्र बहाल हो सकता है, जिससे ओवीएल को अपने पुराने बकाये की वसूली में सहायता मिलेगी।

ट्रंप की तेल उद्योग को नियंत्रित, पुनर्जीवित करने की योजना के समक्ष बड़ी चुनौतियां

वाशिंगटन, 4 जनवरी (एपी)।

राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना द्वारा पकड़ लिए जाने के बाद वेनेजुएला के तेल उद्योग पर नियंत्रण करने और अमेरिकी कंपनियों द्वारा इसे पुनर्जीवित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना का तेल की कीमतों पर तत्काल कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

वेनेजुएला का तेल उद्योग उपेक्षा और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण जर्जर स्थिति में है। इसलिए उत्पादन में तेज बढ़ोतरी होने में कई साल लगेंगे और बड़े निवेश की जरूरत होगी। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि वेनेजुएला 11 लाख बैरल प्रतिदिन के अपने वर्तमान उत्पादन को दोगुना या तिगुना करके जल्दी ही ऐतिहासिक स्तर तक लौट सकता है। गैसबडी के प्रमुख पेट्रोलियम विश्लेषक पैट्रिक डी हान ने कहा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई से वेनेजुएला के तेल उद्योग को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह कई सालों से खराब स्थिति में था और इसे फिर से ठीक होने में समय लगेगा। अमेरिकी तेल कंपनियां तब ही भारी निवेश करेंगी जब देश में स्थिर सरकार होगी।

ट्रंप ने कहा कि सब कुछ अमेरिका के नियंत्रण में है, जबकि वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्ज ने उच्च न्यायालय के आदेश से अस्थायी राष्ट्रपति बनने से पहले यह कहा कि मादुरो को सत्ता में लौटना चाहिए। प्राइस फ्यूचर्स ग्रुप के वरिष्ठ बाजार विश्लेषक फिल फ्लिन ने कहा कि अगर अगले 24 घंटे में यह लगे कि अमेरिका, देश (वेनेजुएला) को सफलतापूर्वक चला रहा है, तो अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों के जल्दी ही वहां के तेल उद्योग को फिर से सक्रिय करने की संभावना होगी।

उन्होंने कहा कि अगर वेनेजुएला अपना तेल उत्पादन बढ़ा लेता है, तो इससे लंबे समय तक तेल सस्ता रह सकता है और रूस पर भी दबाव बढ़ सकता है। सप्ताहांत में तेल का व्यापार नहीं होता, इसलिए कीमतों पर तुरंत कोई असर नहीं पड़ा।

Jansatta Page No-10

तनाव

विश्व के कई देश अशांति और संघर्ष से जूझ रहे

वर्तमान में दुनिया अत्यंत अस्थिर दौर से गुजर रही है। हर महाद्वीप संघर्ष व तनाव के केंद्र बने हुए हैं। एशिया, अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण अमेरिका क्षेत्रों में कोई न कोई देश सशस्त्र संघर्ष या हमले से जूझ रहा है। विश्व के प्रमुख संघर्ष क्षेत्रों की स्थिति पर एक नजर।

1 द. अमेरिका : वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई

अमेरिका ने तीन जनवरी को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला पर हमले किए। अमेरिका इसे नारको-आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई बता रहा है। वहीं, रूस-चीन इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे हैं।

2 यूरोप: रूस-यूक्रेन युद्ध

फरवरी 2022 में शुरू हुआ संघर्ष चौथे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यह केवल दो देशों का युद्ध नहीं रहा, बल्कि रूस-नाटो के बीच छद्म युद्ध बन चुका है, जिसने पूरे यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया है। रूस ने यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा जमा रखा है।

3 पश्चिम एशिया

सऊदी अरब-यूएई आमने-सामने

सूडान का गृहयुद्ध अब दो खाड़ी देशों सऊदी अरब-यूएई के बीच क्षेत्रीय प्रभुत्व की लड़ाई बन गया है। वे सीधे तौर पर लड़ने की जगह दो अलग-अलग गुटों को समर्थन दे रहे हैं।

इजरायल-गाजा संघर्ष

अक्तूबर 2023 से शुरू हुआ था। अभी यहां सीजफायर है पर जमीन पर शांति अभी भी कोसों दूर है। इस संघर्ष में अब तक 46 हजार से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं।

सीरिया में ब्रिटेन-फ्रांस का हमला

सीरिया में ब्रिटेन और फ्रांस के युद्धक विमानों ने भूमिगत ठिकाने पर हवाई हमला किया। यहां इस्लामिक स्टेट समूह के सदस्यों द्वारा विस्फोटक जमा किए जाने का संदेह है।

ईरान में हिंसक विरोध-प्रदर्शन

ईरान में एक हफ्ते से हिंसक विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। यह सिर्फ राजनीतिक नहीं, आर्थिक संकट का परिणाम है। क्योंकि देश की मुद्रा रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गई है।

4 एशिया

चीन-ताइवान में भारी तनाव

चीन-ताइवान के बीच तनाव उच्चतम स्तर पर है। हाल के दिनों में चीन की सैन्य गतिविधियों व कड़े बयानों ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में युद्ध की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। चीन ने हाल ही में ताइवान की घेराबंदी करते हुए 'जस्टिस मिशन 2025' नाम से एक सैन्य अभ्यास संपन्न किया। चीन के कोस्ट गार्ड ने ताइवान के नियंत्रण वाले किनमेन द्वीप के पास गश्त बढ़ा दी है, जिसे ताइवान की संप्रभुता के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है।

5 दक्षिण एशिया : भारत-पाक के बीच तनाव

पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए 7 मई, 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इसके तहत पाक के बहावलपुर व मुरीदके के अंदर तक घुसकर आतंकी मुख्यालयों को निशाना बनाया गया। युद्ध में पाक को भारी नुकसान हुआ।

Hindustan Page No-13

भारतीय सेना की नई ड्रोन आर्मी तैयार, दुश्मन के अड्डों पर हमला करने में है माहिर

एक लाख ड्रोन ऑपरेटर के साथ भैरव फोर्स राजस्थान में तैनात

बदलाव

नसीराबाद(राजस्थान), एजेंसी। देश की सुरक्षा और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने अब तक का सबसे बड़ा बदलाव किया है। सेना ने एक ऐसी टीम तैयार की है जिसमें एक लाख से अधिक ड्रोन चलाने वाले सैनिक (ड्रोन ऑपरेटर्स) शामिल हैं। इसके साथ ही, आधुनिक युद्ध के लिए 'भैरव' नाम की एक नई स्पेशल फोर्स भी बनाई गई है। इस फोर्स में शामिल सभी सैनिक ड्रोन चलाने और उनके जरिए दुश्मन के अड्डों पर हमला करने में माहिर हैं।

अब तक 15 बटालियन बनी : सेना ने ऐसी 15 बटालियन बना ली हैं। आने वाले समय में कुल 25 बटालियन बनाने की योजना है। ये सैनिक दोनों सीमाओं (चीन और पाकिस्तान) पर तैनात किए जाएंगे। ये बटालियन 'पैरा स्पेशल फोर्स' और 'नियमित पैदल सेना' के बीच की कड़ी के रूप में काम करेंगी। ये तेजी से और आक्रामक तरीके से हमला करने में सक्षम हैं।

रेगिस्तानी इलाकों के लिए विशेष तैयारी : राजस्थान के नसीराबाद में तैनात '2 भैरव बटालियन' को 'डेजर्ट फाल्कन्स' कहा जाता है। बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने बताया कि इसे सन्स ऑफ द सॉइल के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है, क्योंकि इसमें ज्यादातर सैनिक राजस्थान के ही हैं। ये राजस्थान के मौसम, भाषा और इलाके को अच्छी तरह समझते हैं। बटालियन को राजंघन की बहादुरी और वीरता की विरासत पर बनाया गया है, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कमांडिंग ऑफिसर ने बताया कि आज के युद्ध तकनीक पर आधारित हैं। 'भैरव' को एक ऐसी ताकत के रूप में विकसित किया गया है जो से दुश्मन के इलाके में घुसकर तकनीक और बहादुरी के साथ ऑपरेशन कर सकती है। ये 'भैरव' बटालियन पहली बार 15 जनवरी 2026 को जयपुर में होने वाली सेना दिवस परेड में हिस्सा लेंगी।

रुद्र ब्रिगेड भी बनाई: सेना ने 'रुद्र ब्रिगेड' भी बनाई है। इसमें पैदल सेना, टैंक, तोपें और ड्रोन—सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। आर्टिलरी, मशीनीकृत इन्फैंट्री और आर्मर्ड कोर को भी ड्रोन और अन्य क्षमताओं जैसे युद्ध उपकरणों से लैस किया जा रहा है।

कड़ा प्रशिक्षण मिला

भैरव बटालियनों ने पिछले पांच महीनों में अपनी स्थापना के बाद से बहुत कड़ी ट्रेनिंग ली है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और एक्सरसाइज अखंड प्रहार के दौरान सफल ऑपरेशन किया है। इस दौरान सैनिकों ने दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की मौजूदगी में अपनी तैयारी दिखाई।

तकनीक से लैस

आधुनिक युद्ध बहुत तेजी से बदल रहा है। आज के संघर्ष हाइब्रिड प्रकृति के हैं, और चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक से पूरी तरह लैस होना जरूरी है। भैरव बटालियनों को आधुनिक तकनीक, नई सोच प्रक्रिया और नई परिचालन जरूरतों के अनुसार गठित किया गया है। -कमांडिंग ऑफिसर, 2 भैरव बटालियन

01 लाख ड्रोन ऑपरेटर और नई स्पेशल फोर्स 'भैरव' तैयार

25 बटालियन बनाने की योजना है आने वाले समय में

Hindustan Page No-7

धुरंधर 800 करोड़ कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म बनी

उपलब्धि

नईदिल्ली, एजेंसी। बहुचर्चित फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसकी कल्पना कम ही की जा रही थी। रिलीज के 30वें दिन यानी पांचवें शनिवार को फिल्म ने भारत में 800 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।

यह फिल्म 800 करोड़ रुपये कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म है। रिपोर्ट के अनुसार, अब तक बॉक्स ऑफिस पर हिंदी फिल्मों के लिए यह मुकाम दूर का सपना माना जाता था, लेकिन 'धुरंधर' ने तमाम अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए इंडस्ट्री में नई उपलब्धि हासिल की। ट्रेड पंडितों की मानें तो फिल्म अब सीधे तौर पर 'पुष्पा 2' के हिंदी लाइफटाइम रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है, जो फिलहाल 836 करोड़ रुपये पर टिका हुई है।

पुष्पा 2 हिंदी में 800 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म (डब) है, लेकिन धुरंधर 800 करोड़ कमाने वाली पहली हिंदी (बॉलीवुड) फिल्म है। आमतौर पर बड़ी फिल्में चौथे या पांचवें हफ्ते तक आते-आते रफ्तार खो देती हैं, लेकिन 'धुरंधर' इस मामले में सबसे आगे है।

05 वें शनिवार को फिल्म ने भारत में कमाई का रिकॉर्ड बनाया

फिल्म 'दशावतार' ऑस्कर 2026 की दौड़ में शामिल

मुंबई। फिल्म 'दशावतार' ऑस्कर दावेदारी सूची के लिए आधिकारिक तौर पर चुनी जाने वाली पहली मराठी फिल्म बन गई है। फिल्म के निर्देशक सुबोध खानोलकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये यह जानकारी दी। दशावतार ने ऑस्कर स्क्रीनर्स रूम मे प्रदर्शित होने वाली पहली मराठी फिल्म बनकर एक और उपलब्धि हासिल की है। एकेडमी के सदस्य वहां फिल्म देखेंगे। वहीं, खानोलकर ने कहा कि इसने पूरी टीम की वर्षों की कड़ी मेहनत को मान्यता दी।

Hindustan Page No-14

Jansatta Page No-1

अमेरिका-वेनेजुएला विवाद गहराया | वैश्विक संकट | आर्थिक शोध संस्थान जीटीआरआइ ने कहा

भारत के व्यापार पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जनवरी।

वेनेजुएला के साथ अमेरिका का विवाद गहराने के बाद कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। वेनेजुएला में विश्व का सबसे बढ़ा कच्चा तेल भंडार है और वर्ष 2025 में वेनेजुएला ने नौ लाख बैरल प्रतिदिन वैश्विक आपूर्ति की। भारत भी वेनेजुएला से तेल का आयातक है, इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका-वेनेजुएला विवाद का भारत के व्यापार पर असर पड़ सकता है। शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआइ) ने रविवार को कहा कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच विवाद का भारत के वेनेजुएला के साथ व्यापार पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।

अमेरिकी सेना ने चार जनवरी को वेनेजुएला में बड़ी सैन्य कार्रवाई की, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया। जीटीआरआइ के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि भारत के लिए इसका आर्थिक या ऊर्जा क्षेत्र पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत-वेनेजुएला व्यापार पहले ही काफी घट चुका है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात 81.3 फीसद घटकर 2.55 अरब डालर रह गया, जबकि कुल व्यापार भी मामूली स्तर पर ही रहा। भारत का वेनेजुएला को दवा सहित अन्य उत्पादों का निर्यात 9.53 करोड़ डालर का रहा। श्रीवास्तव ने कहा कि भारत और वेनेजुएला के बीच व्यापार अब घटता जा रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण अमेरिकी प्रतिबंध और व्यापारिक गतिविधियों में कमी है। उन्होंने यह भी कहा कि कम व्यापार, सख्त प्रतिबंध और बड़ी दूरी को देखते हुए वेनेजुएला की हाल की घटनाएं भारत की अर्थव्यवस्था या ऊर्जा सुरक्षा पर कोई बड़ा असर नहीं डालेंगी।

उल्लेखनीय है कि भारत वेनेजुएला को फार्मास्युटिकल एत्पाद, मशीनरी, कपड़े आदि का निर्यात करता है, जबकि वहां से कच्चे तेल का आयात करता है। वर्ष 2013 भारत के कुल तेल आयात में वेनेजुएला की हिस्सेदारी दस प्रतिशत थी। दूरी व अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण वर्ष 2019 में आयात हिस्सेदारी घटकर 5.9 फीसद और वर्ष 2020 में 3.6 फीसद रह गई। चूंकि भारत वेनेजुएला से तेल का बहुत कम आयात करता है और दोनों देशों के बीच व्यापार पर भी बहुत कम है, इसलिए अमेरिका के साथ उसके विवाद का भारत के व्यापार व तेल व्यापार पर बहुत अधिक असर नहीं पड़ेगा।

पिछले वर्ष जरूर भारत व वेनेजुएला के बीच डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र समझौता हुआ था। वेनेजुएला के तेल दोहन पर अगर अमेरिकी नियंत्रण कायम होता है तो भारत के साथ व्यापार संबंध नए सिरे से विकसित होंगे।

जीटीआरआइ के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि भारत के लिए इसका आर्थिक या ऊर्जा क्षेत्र पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत-वेनेजुएला व्यापार पहले ही काफी घट चुका है।
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात 81.3 फीसद घटकर 2.55 अरब डालर रह गया, जबकि कुल व्यापार भी मामूली स्तर पर ही रहा।

दुधवा में मेहमान पक्षियों की नई प्रजातियां दिखीं

लखीमपुर, संवाददाता। दुधवा टाइगर रिजर्व में सर्दियों के इस मौसम में दूर देश से सात समंदर पार कर मेहमान पक्षियों की प्रजातियां यहां आ रही हैं। तमाम ऐसी प्रजातियां भी हैं जो पहली बार दुधवा आई हैं तो कई ऐसी भी हैं, जो लगातार दुधवा के जंगल में आ रही हैं। अब इन सभी पक्षियों की प्रजातियों का डिजिटल डाटा बेस तैयार किया जाएगा। इसके लिए विशेष टीमें पक्षियों की फोटो के साथ डाटा तैयार करेंगी।

हर वर्ष पांच जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विलुप्त हो रही पक्षी प्रजातियों के संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाना है। दुधवा टाइगर रिजर्व में 400 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कई विदेशी प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं। सर्दियों में साइबेरियन देशों से आने वाली सौ से ज्यादा पक्षी प्रजातियां दुधवा पहुंचती हैं और यहीं वंश वृद्धि भी करती हैं। दुधवा प्रशासन हर साल पक्षियों की मौजूदगी को लेकर सर्वे कराता है। इस बार भी मेहमान पक्षियों का सर्वे जारी है।

इस सर्वे में दुधवा का स्टाफ और बायोलॉजिस्टों की टीम झादी ताल, सठियाना और बांके ताल जैसे प्रमुख जलाशयों के आसपास पक्षियों की गणना और पहचान करती है।

Hindustan Page No-14

वाराणसी में राष्ट्रीय वालीबाल के उद्घाटन कार्यक्रम से आभासी रूप से जुड़े प्रधानमंत्री ने कहा

ओलंपिक मेजबानी की तैयारी कर रहा भारत

वाराणसी, 4 जनवरी (जनसत्ता)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि पिछले साढ़े 11 वर्षों में सरकार ने देश में खेलों के क्षेत्र में व्यापक बदलाव करते हुए 20 से अधिक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित किए हैं और भारत 'पूरी मजबूती से' 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की भी तैयारी कर रहा है।

वाराणसी में रविवार से शुरू हुई 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वालीबाल चैंपियनशिप के उद्घाटन कार्यक्रम से आभासी रूप से जुड़े प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में कई शहरों में फीफा अंडर-17 विश्व कप और हाकी विश्व कप समेत 20 से अधिक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित किए गए हैं। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भी भारत में ही होने जा रहे हैं। भारत पूरी मजबूती से 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की भी तैयारी कर रहा है। इसके पीछे प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को खेलने के अधिक से अधिक मौके मिलें। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़े व्यापक सुधार किए हैं।

उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़े व्यापक सुधार किए हैं। राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम और खेलो भारत नीति 2025 - इस प्रकार के प्रावधानों से सही प्रतिभा को अवसर मिलेगा, खेल संगठनों में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही देश के युवाओं को खेल और शिक्षा दोनों ही क्षेत्र में एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी में अलग-अलग खेलों से जुड़े स्टेडियम बन रहे हैं। नए खेल परिसर में आसपास के जिलों के खिलाड़ियों को भी प्रशिक्षण का मौका मिल रहा है।

राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम और खेलो भारत नीति 2025 इस प्रकार के प्रावधानों से सही प्रतिभा को अवसर मिलेगा, खेल संगठनों में पारदर्शिता बढ़ेगी और साथ ही देश के युवाओं को खेल और शिक्षा दोनों ही क्षेत्र में एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। एक तरफ हम अच्छा मूलभूत ढांचा और वित्त पोषण का तंत्र तैयार कर रहे हैं और उसके साथ ही नौजवानों को शानदार अनुभव देने के लिए भी काम कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि एक समय था जब खेलों को लेकर सरकार और समाज दोनों में ही उदासीनता का माहौल था। बहुत कम युवा खेल को करिअर की तरह अपनाते थे लेकिन बीते दशक में खेलों को लेकर सरकार और समाज दोनों की ही सोच में बदलाव दिख रहा है।

प्रधानमंत्री ने खेलों के क्षेत्र में अपनी सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि हम स्कूल स्तर पर भी खिलाड़ियों को ओलंपिक का अनुभव देने में जुटे हैं। खेलो इंडिया अभियान की वजह से सैकड़ो युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर आगे आने का मौका मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही सांसद खेल महोत्सव का भी आयोजन हुआ है। इसमें भी करीब एक करोड़ युवाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई। सांसद खेल महोत्सव के दौरान मेरी काशी के भी करीब तीन लाख युवाओं ने मैदान पर अपना दमखम दिखाया।

मोदी ने कहा कि वाराणसी में अलग-अलग खेलों से जुड़े स्टेडियम बन रहे हैं। नए खेल परिसर में आसपास के जिलों के खिलाड़ियों को भी प्रशिक्षण का मौका मिल रहा है। मुझे खुशी है कि काशी बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार हो रही है। वालीबाल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के जरिए देश के खेल नक्शे पर जगह बनाना भी काशी के लिए बहुत अहम है। प्रधानमंत्री ने वालीबाल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल हो रहे खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि देश के 28 राज्यों की टीमें यहां आई हैं। आप सब 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की बहुत सुंदर तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय वालीबाल चैंपियनशिप के दौरान बनारस का जोश हाई हो जाएगा।

Jansatta Page No-8

अनुलोम-विलोम
बुलेट ट्रेन

रेलवे की सेवा को गति देगी बुलेट ट्रेन

देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना अब अंतिम चरण में दिखती है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि 15 अगस्त, 2027 से देश में पहली बुलेट ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। यह ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद के बीच चलेगी। इस रेलमार्ग परियोजना पर पिछले कई वर्षों से काम चल रहा है। पिछले साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की थी।

देश में बुलेट ट्रेन चलाने के कई फायदे हैं। इन फायदों में समय की बचत, आर्थिक विकास को बढ़ावा, रोजगार सृजन, सड़क यातायात के दबाव व प्रदूषण में कमी और तकनीकी उन्नति शामिल हैं। यह ट्रेन यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और तेज यात्रा का विकल्प देगी, जिससे शहरों के बीच कनेक्टिविटी और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही यह ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल भी होगी और 'मेक इन इंडिया' पहल को मजबूत करेगी।

असल में, देश में उन मार्गों पर बुलेट ट्रेन चलाना बहुत जरूरी और फायदेमंद है, जिन पर पूरे साल भारी भीड़ रहती है। इनमें मुंबई-अहमदाबाद के अलावा, पूर्व और उत्तर रेलवे के मार्ग प्रमुख हैं। दिल्ली से यूपी-बिहार होते हुए हावड़ा व गुवाहाटी तक अगर बुलेट ट्रेनें चलाई जाती हैं, तो इससे रेलवे की आमदनी में तो वृद्धि होगी ही, यात्रियों को भी काफी सहूलियतें होंगी। कम समय में गंतव्य तक पहुंचाने वाली बुलेट ट्रेनों के इन रेल मार्गों पर शुरू होने से आम ट्रेनों की उच्च श्रेणियों में सफर करने वाले यात्री बुलेट ट्रेन को प्राथमिकता देने लगेंगे। जाहिर है, इससे सामान्य ट्रेनों में आम यात्रियों के लिए अधिक सीटें उपलब्ध होने लगेंगी। लोग निजी वाहनों या हवाई जहाज की जगह बुलेट ट्रेन को चुनेंगे, तो इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा और वायु प्रदूषण कम होगा। इस तरह भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क का तनाव घट जाएगा और यात्रा भी सुगम होगी।

बुलेट ट्रेन से लंबी दूरी की यात्राएं बहुत कम समय में पूरी होंगी (जैसे मुंबई-अहमदाबाद का सफर 7-8 घंटे की जगह 3 घंटे से भी कम समय में)। बुलेट ट्रेन की बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे देश का आर्थिक विकास तेज होगा। विकसित देशों में बुलेट ट्रेनें उच्च सुरक्षा मानक और आरामदेह यात्रा के लिए जानी जाती हैं। भारत में जापानी तकनीक के साथ भारतीय कल-पुर्जों का उपयोग 'मेक इन इंडिया' पहल को भी मजबूती प्रदान करेगा। इस तरह हम जल्द ही पाएंगे कि विकसित होते भारत में अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाली बुलेट ट्रेनें अनिवार्य साधन बन गई हैं।

ओम बाबू, छात्र

पहले सामान्य ट्रेनों की हालत सुधारिए

बहुत दिनों से बुलेट ट्रेन का शिगूफा सुनते आ रहे हैं, अब रेल मंत्री ने एक नया डेट दिया है कि 15 अगस्त, 2027 को यह कमाल हो जाएगा। मगर इस रेलगाड़ी का गुणगान करने से पहले क्या रेल विभाग आम रेलगाड़ियों की दशा-दुर्दशा का लेखा-जोखा पेश करेगा? एक चमकती तस्वीर दिखाकर भारतीय रेल अपनी बदहाली को नहीं छिपा सकता। गुजरे साल के पहले महीने में ही महाराष्ट्र के जलगांव में हुई दुर्घटना में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और अनेक लोग घायल हुए थे। इसके अगले महीने 15 फरवरी को तमाम दावों के बावजूद कुंभ मेले में जाने वाले 18 श्रद्धालुओं को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपनी जान गंवानी पड़ी। कई सारे लोग वहां मची भगदड़ में बुरी तरह जख्मी हुए। अभी 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेल दुर्घटना में 12 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा घायल हो गए। 20 दिसंबर को सैरांग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ने आठ हाथियों की बलि ले ली।

ये दुर्घटनाएं आसमानी कहर का परिणाम नहीं थीं, ये भारतीय रेलवे की खामियों और अक्षमता का नतीजा थीं। घंटों विलंब से चलती ट्रेनें, आज भी अनेक स्टेशनों पर बजबजाती गंदगी और रेलगाड़ियों के पैंट्री कार की बदइंतजामी की खबरें लगभग हर हफ्ते किसी न किसी अखबार या टीवी चैनल पर साया होती हैं। तो क्या बुलेट ट्रेन से ज्यादा आम रेलगाड़ियों की हालत सुधारने की जरूरत नहीं है? आखिर क्यों हमारी तरक्की संपन्न लोगों की सुविधाओं से मापी जाने लगी है? एक तरफ, 80 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को पांच किलो राशन देने की मजबूरी गिनाई जा रही है और दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन की शोशेबाजी पेश की जा रही है। यह हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि बहुमत अब भी अपनी सुविधाओं के लिए सवाल पूछना नहीं सीख सका है। जब तक जनता सवाल पूछना नहीं शुरू करेगी, सरकारें अपनी प्राथमिकता में उनके लिए पांच किलो राशन और सरमायेदारों के लिए लाखों करोड़ रुपये की रेवड़ियां व बुलेट ट्रेन ऊपर रखेंगी।

भारतीय रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत भी बड़े गज-धज के साथ की थी, लेकिन वे कितने फायदे में चल रही हैं, यह तो रेल महकमा ही बताएगा। सच यह है कि बुलेट ट्रेन से पहले हरेक शहर को अच्छी मेट्रो सेवाओं और लंबी दूरी की ट्रेनों में साफ-सुथरे शौचालय व पैंट्री कार की दरकार है। दुर्योग से रेलवे के बड़े ओहदेदारों की निगाह इस ओर जाती ही नहीं। उन्हें बुलेट ट्रेन चलाने का तमगा सिर्फ अपने नाम करना है। मगर इससे रेल महकमे की नाकामियां कभी नहीं छिपेंगी।

राम्या सिंह राजावत, टिप्पणीकार

Hindustan Page -10

जरूरी है तंबाकू पर पूर्ण विराम

देवेंद्रराज सुथार

सरकार एक फरवरी से सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर उपकर और शुल्क बढ़ाने जा रही है। यानी तंबाकू महंगा होगा। सरकार का तर्क है कि इससे अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, जो स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर खर्च किया जा सकेगा। साथ ही महंगा होने से तंबाकू का उपयोग भी कम होगा। इसका आशय है कि हम तंबाकू को 'महंगा जहर' बनाकर रखेंगे और इसे समाज से पूरी तरह बाहर नहीं करेंगे।

तंबाकू एक साधारण उपभोग वस्तु नहीं, यह धीमी हत्या का औजार है। निकोटिन शरीर और मस्तिष्क पर ऐसी निर्भरता पैदा करता है कि व्यक्ति जानते-बूझते हुए भी इससे मुक्त नहीं हो पाता। कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, अस्थमा, दांत और मसूड़ों की बीमारियों की जड़ में कहीं न कहीं तंबाकू मौजूद रहता है। हर साल लाखों परिवार अपने किसी सदस्य को इस जहर के कारण खोते हैं, लेकिन इस त्रासदी के बावजूद तंबाकू का कारोबार लगातार बढ़ता है। कंपनियां नए-नए आकर्षक पैकेट, फ्लेवर और उत्पाद पेश कर युवाओं को फंसाती हैं और समाज में इसे सामान्य और स्वीकार्य बनाए रखने की कोशिश करती हैं। यह सब इस तथ्य के बावजूद होता है कि तंबाकू अपने उपयोगकर्ता के साथ-साथ उसके परिवार और पूरे स्वास्थ्य ढांचे पर बोझ डालता है।

कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, अस्थमा, दांत और मसूड़ों की बीमारियों की जड़ में कहीं न कहीं तंबाकू मौजूद रहता है

कहा जाता है कि तंबाकू पर कर बढ़ाने से खपत घटती है। यह आंशिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। जिन लोगों में लत गहरी है, वे कीमत बढ़ने पर भी सेवन जारी रखते हैं। वे सस्ती और घटिया क्वालिटी के उत्पादों की ओर मुड़ जाते हैं या अवैध स्रोतों से खरीदते हैं। इस तरह कर नीति तंबाकू सेवन को समाप्त नहीं करती, बस उसे नए रास्ते दे देती है। इससे अवैध व्यापार, तस्करी और अपराध को भी बढ़ावा मिलता है। साथ ही सरकार को मिलने वाला राजस्व उसके लिए एक आर्थिक सहारा बन जाता है और फिर इस घातक उद्योग से दूरी बनाना और कठिन हो जाता है। इस तरह सार्वजनिक स्वास्थ्य और सरकारी आय के बीच एक विचित्र नैतिक टकराव खड़ा हो जाता है।

जब कोई चीज कानूनी रूप से स्वीकार्य रहती है तो उसकी सामाजिक स्वीकृति भी बनी रहती है। बच्चे और युवा यह मान लेते हैं कि यदि यह खुलेआम बिक रही है तो यह उतनी हानिकारक नहीं होगी, लेकिन प्रतिबंध समाज को यह संदेश देता है कि यह पदार्थ हमारे जीवन का हिस्सा बनने के योग्य ही नहीं। यह सोच बदलना सबसे बड़ा सुधार होगा। मीडिया, शिक्षा, परिवार और समुदाय सभी स्तरों पर यह चेतना मजबूत होनी चाहिए कि तंबाकू से दूरी केवल व्यक्तिगत चुनाव नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी है। तंबाकू उत्पादन, विपणन और बिक्री को वैधानिक ढांचे से बाहर करना जरूरी है, क्योंकि जब तक बाजार मौजूद है, तब तक लत का चक्र चलता रहेगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

ईरान से नजदीकी बढ़ा रहा था वेनेजुएला, इसलिए कार्रवाई थी जरूरी : रूबियो

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वेनेजुएला में की गई सैन्य कार्रवाई को जरूरी बताया। कहा, वेनेजुएला ईरान से नजदीकी बढ़ा रहा था। वहां आपराधिक समूहों को मनमानी की छूट मिली हुई थी। अमेरिका को इससे खतरा बढ़ रहा था। कहा, इस मामले की तुलना इराक, लीबिया या अफगानिस्तान से नहीं की जा सकती है। वेनेजुएला में तत्काल लोकतांत्रिक सत्ता परिवर्तन की उम्मीदों को अवास्तविक बताते हुए कहा, मादुरो की गिरफ्तारी के तुरंत बाद चुनाव की मांग व्यावहारिक नहीं है।

▸ विदेश मंत्री बोले, वेनेजुएला के तेल हितों से अमेरिकी नीति संचालित नहीं

रूबियो ने कहा कि मारिया मचाडो के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान है

समाचार एजेंसी आइएएनएस के मुताबिक, रूबियो ने वेनेजुएला के तेल भंडार पर अमेरिकी नजर के दावों को भी खारिज किया। कहा, तेल हितों से अमेरिकी नीति संचालित नहीं होती। हमने एक नार्को तस्कर को पकड़ा है। हालांकि, उन्होंने वेनेजुएला की आर्थिक बेहतरी में तेल को केंद्रीय भूमिका में बताया। कहा,तेल उद्योग बुरी तरह तबाह हो चुका है। उन्हें निवेश की जरूरत है। तेल संपदा से जनता का ही भला होगा। फिलहाल, वहां की समस्त संपदा चुरा ली गई है। उन्होंने वेनेजुएला में विपक्षी नेताओं की भूमिका को भी स्वीकारा। उन्होंने कहा कि मारिया कोरिना मचाडो के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान है। साथ ही एडमुंडो गोंजालेज की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन में समय लगेगा। ये एक प्रक्रिया के तहत होगा।

रक्षा मंत्री हेगसेथ ने कहा, वेनेजुएला की तुलना इराक से करना अनुचित: अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने वेनेजुएला में कार्रवाई की 2003 के इराक हमले से तुलना को अनुचित बताया। कहा,मादुरो का मामला इराक के सर्वथा उलट है। वेनेजुएला में आपरेशन मौजूदा रणनीति सैनिकों को खतरे में डाले बिना लक्ष्य हासिल करने पर केंद्रित है। बता दें कि 2003 में इराक में अमेरिका ने हमला किया था और तानाशाह राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया था। 2006 में इराकी कोर्ट ने मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए सद्दाम को फांसी की सजा दी गई थी।

ट्रंप की नजर वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर

प्रथम पृष्ठ से आगे

वहीं, ट्रंप ने दावा किया कि इस कार्रवाई से अमेरिका को वेनेजुएला को चलाने व उसके विशाल तेल भंडार के उपयोग का अवसर मिलेगा। अमेरिकी तेल कंपनियां वापसी करेंगी और बुरी हालत में पहुंच चुके तेल ढांचे की मरम्मत करेंगी। इसमें कई साल लग सकते हैं। कहा, वेनेजुएला में वामपंथी शासन से अमेरिकी कंपनियों को काफी नुकसान पहुंचा है।

ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही थी तख्तापलट की योजना: सीएनएन से बातचीत में अमेरिका के पूर्व एनएसए जान बोल्टन ने दावा किया कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही वेनेजुएला पर हमले की योजना तैयार की गई थी। इसकी प्रस्तुति भी दी गई थी, पर तब ट्रंप इस पर फोकस नहीं कर पाए।

सुरक्षा परिषद की आपात बैठक आज : अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई की वैधता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कोलंबिया के प्रस्ताव पर सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर आपात बैठक प्रस्तावित है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इसे खतरनाक मिसाल बताया है।

कराकास में तनावपूर्ण शांति, जश्न मनाने में भी डर रहे लोग : अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से मचे हड़कंप के बाद रविवार को वेनेजुएला में तनावपूर्ण शांति रही। काराकास में सन्नाटा रहा। सड़कों पर गाड़ियां कम दिखीं। किराना दुकानें, पेट्रोल पंप व अन्य प्रतिष्ठान बंद रहे। हालांकि विपक्षी दलों में अमेरिकी कार्रवाई को लेकर खुशी का माहौल है। लोगों ने देश में तानाशाही के अंत पर खुशी मनाई। पूर्वी काराकास के एक गरीब इलाके में निर्माण मजदूर डैनियल मेडाला ने बताया कि सुरक्षा कारणों से चर्च में सुबह की प्रार्थना नहीं हुई। उनके अनुसार लोग जश्न मनाने से भी डर रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनावों के बाद हुए कड़े दमन की यादें अब भी ताजा हैं।

Dainik jagaran Page No-11

रूस से व्यापार घाटा कम करना बड़ी चुनौती

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान करीब 60 अरब डालर रहा भारत का रूस के साथ व्यापार घाटा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: दिसंबर 2025 में रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच सालाना बैठक में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी गई। द्विपक्षीय कारोबार को ज्यादा संतुलित बनाने यानी भारत से रूस को होने वाले निर्यात को बढ़ाने पर सहमति बनी। हाल ही में इसको लेकर भारत-रूस के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। शुरुआती वार्ता में यह बात सामने आई है कि भारत से रूस को निर्यात बढ़ाने की चुनौती सोच से कहीं ज्यादा है। वजह यह है कि रूस के आयात बास्केट (रूस का कुल आयात) में 80 प्रतिशत हिस्से को भारत ने कभी छुआ ही नहीं है। इसमें मशीनरी, उपकरण, परिवहन उपकरण, इलेक्ट्रिकल उपकरण, चिप्स व सेमीकंडक्टर, रसायनिक उत्पाद आदि हैं। इन सभी चीजों के आयात के लिए रूस 60-70 प्रतिशत तक चीन पर निर्भर है।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि रूस की अगुवाई वाली ईस्टर्न यूरेशियन इकोनमिक यूनियन (ईएईयू) और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर होने वाली वार्ता में ये मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। ईएईयू में रूस के अलावा आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच व्यापार रिकार्ड 68.7 अरब डालर तक पहुंच गया, जो महामारी से पहले के स्तर से लगभग 5.8 गुना अधिक है। इसमें भारत का आयात (मुख्य रूप से कच्चा तेल, उर्वरक और कोयला) 63.8 अरब डालर के आसपास रहा, जबकि निर्यात केवल 4.9 अरब डालर था। भारत का रूस के साथ व्यापार घाटा लगभग 60 अरब डालर के करीब पहुंच गया है, जो मुख्य रूप से रूस से भारी मात्रा में कच्चे तेल के आयात के कारण पैदा हुआ है। रूस का कुल आयात वर्ष 2024-25 में 280 अरब डालर रहा है। इसमें 50 प्रतिशत हिस्सा मशीनरी व रक्षा उपकरण, 20 प्रतिशत इलेक्ट्रिक उपकरण, 10 प्रतिशत वाहन उत्पादों का है।

68.7 अरब डालर रहा पिछले वित्त वर्ष में भारत और रूस के बीच कुल कारोबार

280 अरब डालर का वस्तु आयात किया रूस ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान

- द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ाने के लिए भारत और रूस ने शुरू की वार्ता
- शुरुआती वार्ता में व्यापार घाटे को कम करने की मुश्किलें आई सामने
- रूस के 80 प्रतिशत आयात में भारत की कोई हिस्सेदारी नहीं

दवा बाजार में हिस्सेदारी बढ़ा सकता है भारत

रूस के कुल कारोबार में दवाओं की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत है और भारतीय कंपनियों को इस बाजार में बड़ी हिस्सेदारी मिलने की संभावना है। इसी तरह से रसायन व रबर आयात भी रूस में बढ़ रहा है, जहां भारतीय कंपनियों की नजर है। लेकिन इनका निर्यात बढ़ाकर भी 60 अरब डालर का व्यापार घाटा पूरा होता नहीं दिख रहा है। खाद्य सामग्रियों जैसे- चावल, चाय और मसालों में भी संभावनाएं हैं, लेकिन यहां भी यूरोपीय संघ और अमेरिका के प्रतिबंध इन प्रयासों को बाधित कर रहे हैं।

रूस से कारोबार बढ़ाने पर अमेरिकी प्रतिबंधों का डर

सूत्रों के मुताबिक, भारत मशीनरी व परिवहन उपकरणों का निर्यात तो रूस को कर सकता है लेकिन समस्या यह है कि इस क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां अमेरिका व यूरोपीय बाजारों में भी भारी निर्यात करती हैं। रूस से कारोबार करने पर उन्हें अमेरिकी व पश्चिमी देशों के प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। यह बड़ी वजह है कि भारत व रूस के बीच आपसी करेंसी में कारोबार करने को लेकर भी अधिकांश कंपनियां उत्साहित नहीं है। इसके बावजूद फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य सामग्रियों के निर्यात को बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है।

Dainik jagaran Page No-10

25 फसलों की 184 'सुपर सीड्स' से देश में बदलेगी खेती की तस्वीर

जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से निपटने की दिशा में सरकार ने दी उन्नत बीजों की बड़ी सौगात

किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही खाद्य सुरक्षा के लिए साबित होंगे निर्णायक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निकालकर खेती को उत्पादकता और लाभ के नए दौर में ले जाने की दिशा में रविवार को बड़ी पहल की गई। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 फसलों की 184 उन्नत किस्में जारी की, जो परंपरागत तरीके से खेती को अलग कर नवाचार के सहारे नई दिशा दे सकती हैं। ये किस्में अधिक उपज देने के साथ ही कम पानी, कम उर्वरक और प्रतिकूल मौसम में भी बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। ये किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही खाद्य सुरक्षा के लिए निर्णायक साबित हो सकती हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर), राज्य व केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और निजी बीज कंपनियों के संयुक्त प्रयास से विकसित ये किस्में बदलते मौसम, सूखा-बाढ़ और रोग-कीट जैसी चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि खेती की लागत कम कर किसानों की वास्तविक आय में इजाफा करना है।

शिवराज ने कहा कि वर्ष 1969 से आइसीएआर की कुल 7205 फसल किस्मों को मंजूरी दी जा चुकी है। खास बात यह है कि बीते 11-12 वर्षों में ही 3236 नई उच्च उत्पादक किस्में विकसित हुई हैं, जो इस बात का संकेत है कि देश में कृषि अनुसंधान की रफ्तार कई गुना तेज हुई है। अब जारी की गई 184 किस्में इसी शोध-परंपरा का विस्तार हैं, जो किसानों को अधिक उपज, बेहतर गुणवत्ता और जलवायु सहनशीलता का भरोसा देती हैं।

नई किस्मों में सरसों, कुसुम, तिल, मूंगफली, गोभी और अरंडी की 13 नई किस्में तैयार की गई हैं। अधिकतर किस्में ऐसी हैं जो कम अवधि में अधिक दाना भराव और बेहतर तेल प्रतिशत देने में सक्षम हैं। पारंपरिक सरसों जहां औसतन 18-20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है, वहीं नई किस्म की गोवर्धन सरसों से 22-24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन संभव है।

इसी तरह मूंगफली की नई उन्नत किस्म गिरनार की उपज सामान्य मुंगफली की तुलना में 30-40 प्रतिशत ज्यादा हो सकती है। तेल की मात्रा भी 50 प्रतिशत तक अधिक पाई जाती है। इसे अपनाने से तिलहन मिशन के लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी।

इसे रोगों को सहन करने वाली और अलग-अलग क्षेत्रों के लिए उपयोगी माना गया है। यह न सिर्फ किसानों के हित में होगा, बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ाएगा।

नई किस्मों से लाभ

- इनमें बीज, पानी और कीटनाशकों की जरूरत अपेक्षाकृत होगी कम
- रोग-कीट प्रतिरोधी किस्मों से सिंचाई और दवाइयों का खर्च घटेगा
- बेहतर गुणवत्ता की उपज से किसानों को बेहतर दाम मिल सकेंगे

शिवराज सिंह चौहान। फाइल

फसलों की कुल कितनी किस्में

धान और मक्के की कुल 122 किस्में, दलहन की छह, तिलहन की 13, चारा फसलों की 11, कपास की 24, गन्ने की छह और जूट-तंबाकू की एक-एक किस्म जारी की गई।

Dainik jagaran Page No-3

मंथन

दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता

शाकाहारी जनसंख्या तुलनात्मक रूप से अधिक होने के कारण दलहन पर निर्भरता हमारी अधिक है, परंतु हमें इसका आयात करना पड़ता है, इसलिए इसमें नीतिगत सुधार की आवश्यकता है

ज्ञानेश मिश्र
राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय कृषि उत्पाद उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल

अधिकांश अनाज के उत्पादन के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर हो चुका है। कई अनाज का तो हम निर्यात भी कर रहे हैं। परंतु तमाम प्रयासों के बावजूद हमें बड़ी मात्रा में दलहन का आयात करना पड़ रहा है। हालांकि बीते वर्षों में भारत की कृषि नीति में दूरगामी परिवर्तन देखने को मिला है। दालों को भारत की पोषण सुरक्षा और किसान आर्थिक सशक्तीकरण का आधार मानते हुए भारत सरकार ने इस वर्ष बजट में देश को दालों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक धनराशि जारी की। इसके उपरांत भारत सरकार ने 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' और 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' जैसी ऐतिहासिक पहल शुरू की। भारत सरकार का लक्ष्य 11,440 करोड़ रुपये के दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत फसल वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक घरेलू दलहन उत्पादन को 350 लाख टन तक ले जाना और दालों के आयात पर निर्भरता कम करना है।

इन सबके बावजूद वास्तविक स्थिति चिंताजनक है। दलहन किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम कीमत पर अनाज बेचने को मजबूर हैं। इसका बड़ा कारण है शुल्क मुक्त आयात नीति जिस कारण विदेशी दालों की आवक, पिछले वर्ष का बचा स्टाक व इस वर्ष का आयातित दलहन इतना अधिक हो चुका है कि इससे दालों का घरेलू बाजार दबाव में है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने रिकार्ड 73 लाख टन दलहन आयात किया जिसकी अनुमानित लागत 5.5 अरब डालर रही जो किसी भी विकासशील कृषि प्रधान देश के लिए गंभीर संकेत है। अधि स्टाक होने के कारण इस वर्ष 2025-26 में दलहन का आयात घटकर लगभग 45 लाख टन होने की संभावना है, लेकिन यह अभी भी घरेलू किसानों को राहत देने के लिए अपर्याप्त है।

एमएसपी : देश में दलहन में इस समय आने वाली खरीफ फसलों के लिए वर्ष 2025-26 में अरहर आठ हजार रुपये प्रति क्विंटल, मूंग 8,768 प्रति क्विंटल, उड़द 7,800 प्रति क्विंटल और रबी की फसलों के लिए चना 5,875 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल है, किंतु इन दलहनों की कीमतें वास्तविक बाजार में एमएसपी से 10 से 25 प्रतिशत तक कम हैं। देश में अरहर 5,800 से 6,200 रु प्रति क्विंटल तक बिक रही है, जबकि उड़द, मूंग व चना भी इसी दबाव में एमएसपी से नीचे बिक रहे हैं। यह तब हो रहा है जब भारत सरकार ने अरहर, उड़द व मसूर को एमएसपी पर 100 प्रतिशत सरकारी खरीद की योजना 2028-29 तक लागू करने का लक्ष्य घोषित किया गया है, परंतु वर्तमान मूल्य संरचना उस लक्ष्य को कमजोर कर रही है।

देश में आयात शुल्क मुक्त अरहर, उड़द का व 10 प्रतिशत आयात शुल्क के दायरे में आने वाले चना का भी भारी आयात होने का कारण राष्ट्रीय स्तर पर दलहन उत्पादक राज्यों में इसके गहरे प्रभाव दिख रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक जैसे प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों में दलहन की बोआई का क्षेत्रफल घट रहा है। किसान तेजी से अनाज में गेहूं व धान की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि दालों में लागत और जोखिम अधिक जबकि लाभ कम रह गया है। यह प्रवृत्ति जारी रही तो आने वाले वर्षों में देश को दलहन आयात पर और अधिक निर्भर होना पड़ेगा जो आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के विपरीत है।

दुनिया के कई विकसित देशों में दाल उत्पादन पर भारी सब्सिडी दी जाती है, वहीं भारत में किसान बिना पर्याप्त समर्थन के वैश्विक प्रतिस्पर्धा झेल रहे हैं। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ सुझाव राष्ट्रीय हित में अनिवार्य हैं जैसे अरहर व उड़द में 31 मार्च, 2026 तक लागू शुल्क मुक्त आयात नीति को तत्काल समाप्त करते हुए अरहर, उड़द और 10 प्रतिशत के दायरे में आने वाले चना पर न्यूनतम 30 प्रतिशत आयात शुल्क तुरंत लागू किया जाए जैसा कि पीली मटर में किया गया। दलहन व इसके उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्थिर व दीर्घकालिक नीति का ढांचा बनाने की आवश्यकता है।

दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय किसान को मिले पर्याप्त मदद। फाइल

सबसे आवश्यक देश की दलहन आयात नीति की समीक्षा हेतु व देश को दलहन में आत्मनिर्भरता दिलाने के लिए एक राष्ट्रीय समिति गठित की जाए, जिसमें दलहन उत्पादक राज्यों के किसान संगठनों, दलहन दाल व्यापारी प्रतिनिधियों और दाल उद्यमियों को शामिल किया जाए। भारत हर वर्ष दलहन के आयात पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च करता है, जबकि दलहन उत्पादक राज्यों के घरेलू किसान क्षमता रखते हैं कि देश को दालों में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। दालों में आयात नीति में समयानुसार संतुलन, सरकार की एमएसपी खरीद का क्रियान्वयन, किसानों के लिए संरचनात्मक समर्थन और दीर्घकालिक नीतिगत स्थिरता, इन चार स्तंभों पर भारत न केवल दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करेगा, बल्कि वैश्विक दलहन बाजार में भी एक निर्णायक शक्ति बनकर उभरेगा।

आजकल

मुक्त व्यापार समझौतों में डेरी-कृषि का बचाव

भारत ने न्यूजीलैंड के साथ कुछ दिन पहले एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले भारत आस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम (यूके), संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ओमान तथा अन्य देशों के साथ भी इस तरह का समझौता कर चुका है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात को कुछ हैरानी से देखा जा रहा है, जब नवंबर, 2019 में भारत ने स्वयं को रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) से बाहर कर लिया था, जिसमें आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों शामिल थे। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि भारत ने अब इन्हीं देशों के साथ अलग-अलग एफटीए कैसे कर लिया...

डा. अश्विनी महाजन
पूर्व प्रोफेसर, पीजीडीएवी कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

आरसीईपी एक प्रस्तावित व्यापक व्यापार समझौता था, जिसमें मुक्त व्यापार से जुड़े प्रविधान शामिल थे। इसमें 10 आसियान देश आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और भारत के साथ ही 16 देश भागीदार थे। इस समझौते पर लगभग आठ वर्षों तक बातचीत चली। माना जाता है कि भारत ने आरसीईपी से बाहर निकलने का निर्णय इसलिए लिया, क्योंकि समझौते का अंतिम प्रारूप भारत की अपेक्षाओं और हितों के अनुरूप नहीं था। नवंबर, 2019 में आरसीईपी शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए पीएम मोदी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया।

अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने अंतिम क्षण में इस समझौते से पीछे हटने का साहसिक कदम कैसे लिया? संभवतः यह विश्व इतिहास में पहली बार था जब किसी सरकार के मुखिया ने वर्षों की बातचीत और अंतिम मसौदा तैयार होने के बाद भी, शिखर सम्मेलन में अन्य सभी नेताओं के सामने यह घोषणा की कि उनका देश इस समझौते में शामिल नहीं होगा। वास्तव में डेयरी और कृषि ऐसे दो प्रमुख क्षेत्र थे, जिन पर भारत ने कठोर रुख अपनाया। न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया की मांग थी कि आरसीईपी के सदस्य देश अपने डेयरी और कृषि बाजारों को अन्य देशों के लिए खोलें।

अब जब न्यूजीलैंड के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता किया गया है और उसमें भी कृषि तथा डेयरी क्षेत्रों को बाहर रखा गया है तो यह दृष्टिकोण और अधिक पुष्ट हो जाता है कि भारत मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत करते समय अत्यंत सतर्क रहा है और उसने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि और डेयरी को बाहर रखने में सफलता हासिल की है। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत जैसे देश के लिए कृषि और डेयरी की सुरक्षा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। आलोचक अक्सर तर्क देते हैं कि यदि कृषि और डेयरी को मुक्त व्यापार समझौतों में शामिल किया जाए, तो इससे भारतीय कृषि और डेयरी की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

आजीविका और खाद्य सुरक्षा : संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के आंकड़ों के अनुसार, भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा छोटे और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों से आता है, जिनके पास औसतन केवल एक या दो दुधारू पशु होते हैं। इनके लिए दूध केवल अतिरिक्त आय का साधन नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन का आधार है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत की लगभग आधी आबादी कृषि पर निर्भर है और आठ करोड़ से अधिक परिवार यानी 36 करोड़ लोग डेयरी क्षेत्र से जुड़े हैं। इसके विपरीत, अमेरिका और न्यूजीलैंड जैसे देशों में डेयरी एक व्यापार-केंद्रित उद्योग है, जहां उत्पादन का उद्देश्य मुख्यतः निर्यात और मुनाफा होता है, न कि व्यापक ग्रामीण आजीविका। निस्संदेह, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक होने का गौरव प्राप्त है। भारत में अधिक दूध उत्पादन के पीछे प्रमुख कारण यह है कि देश में दुग्ध उत्पादों- विशेषकर दूध के दाम अपेक्षाकृत लाभकारी हैं, जिससे छोटे उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलता है।

यह भी सर्वविदित है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुग्ध उत्पादों, विशेषकर मिल्क पाउडर की कीमतों में भारी अंतर है। यदि न्यूजीलैंड का दूध या दूध पाउडर बिना शुल्क (टैरिफ) के भारत में आने लगे तो घरेलू बाजार में कीमतों में तेज गिरावट आएगी। इसका सीधा परिणाम यह होगा कि देश के लाखों छोटे दुग्ध उत्पादक उत्पादन बंद करने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बने रहने का दर्जा खो देगा, बल्कि यहां एक गंभीर खाद्य सुरक्षा संकट भी उत्पन्न हो सकता है। यह समझना आवश्यक है कि दुनिया का कोई भी देश चाहे वह कृषि उत्पाद हो या दूध, भारत जैसे विशाल देश की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा केवल आर्थिक नहीं, बल्कि आजीविका और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न भी है।

अमेरिका के साथ समझौता : ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद भारत और अमेरिका दोनों ही, एक व्यापक व्यापार समझौते पर पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, इस दिशा में सबसे बड़ी बाधा कृषि क्षेत्र बनकर उभरी है। अमेरिका कई कृषि उत्पादों का अधिशेष उत्पादन कर रहा है, जिसके लिए वह नए विदेशी बाजार तलाश रहा है। यही कारण है कि अमेरिका भारतीय बाजार में अपने कृषि उत्पादों के लिए आक्रामक रूप से प्रवेश चाहता है, जबकि भारत इसका सख्त विरोध कर रहा है। भारत के इस विरोध के पीछे मुख्यतः दो कारण हैं।

यदि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों को बाजार में प्रवेश की अनुमति देता है जो अमेरिकी सरकार द्वारा भारी सब्सिडी से समर्थित हैं तो भारतीय किसान इस असमान प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाएंगे और उत्पादन बंद करने को मजबूर हो सकते हैं। वहीं अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोलने से भारत की जैव-सुरक्षा और बीज संप्रभुता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका के अधिकांश कृषि उत्पाद आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) होते हैं और पेटेंट के अधीन होते हैं। भारत ने लंबे समय से जीएम खाद्य पदार्थों के प्रति सतर्क रुख अपनाया है। मजबूत घरेलू नियंत्रण के बिना जीएम फसलों को अपनाने से किसानों की लागत बढ़ सकती है, बीजों पर निर्भरता गहरी हो सकती है और ऐसे पारिस्थितिकीय जोखिम पैदा हो सकते हैं, जिनकी भरपाई संभव नहीं होगी। इसलिए अमेरिकी व्यापार समझौते के दबाव में जल्दबाजी करने के बजाय भारत के लिए वैज्ञानिक विवेक और स्वदेशी अनुसंधान को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

भारत में डेयरी उद्योग से बड़ी जनसंख्या जुड़ी हुई है, लिहाजा इनके हितों का भी ध्यान रखना होगा। फाइल

विश्व स्तर के बैंकों से मजबूत बनेगी आर्थिकी

सतीश सिंह
आर्थिक मामलों के जानकार

देश में अधिक व्यापक अंतरराष्ट्रीय स्तर के बैंक बनाने के उद्देश्य से सरकार 2026 में फिर से सरकारी बैंकों का विलय कर सकती है। इस समय केवल भारतीय स्टेट बैंक ही संपत्ति के संदर्भ में दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों में शामिल है। सरकार का मानना है कि बड़े बैंक बनाना देश की आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं। वर्तमान में देश में 12 सरकारी बैंक हैं, लेकिन संपत्ति के हिसाब से स्टेट बैंक को छोड़कर वे दुनिया के शीर्ष बैंकों में शामिल नहीं हैं।

वर्तमान में 12 सरकारी बैंकों का कारोबार बैंकिंग क्षेत्र के कुल कारोबार का लगभग 60 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2025-26 के पहले छह महीनों में इन्होंने 93,675 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल के अप्रैल से सितंबर के 85,520 करोड़ रुपये से 10 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2026 के अंत तक यह मुनाफा दो लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर सकता है। वस्तुतः सरकारी बैंकों में सुधार, विलय और बेहतर प्रबंधन से आया है। विदेशी निवेशक भारतीय बैंकों में पैसा लगा रहे हैं। विदेशी निवेशकों द्वारा निजी बैंकों में निवेश का अर्थ है कि विदेशी निवेशकों का भारतीय बैंकिंग प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर भरोसा बढ़ रहा है। सरकारी तंत्रों में पारदर्शिता, नियंत्रण में लचीलापन और बैंकिंग क्षेत्र में सकारात्मक संरचनात्मक प्रवृत्तियों से स्थिति बदल रही है।

सरकार का मानना है कि छोटे बैंकों को सरकारी सहायता की आवश्यकता है, जिससे उनका वित्तीय बोझ बढ़ता है, जबकि बड़े बैंक वैश्विक बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा बन सकते हैं। इससे बैंकों की दक्षता और ग्राहकों तक पहुंच बेहतर होगी। बड़े बैंक दीर्घकालिक रूप से काम कर सकते हैं। जनता का उन पर अधिक भरोसा होता है और बड़े बैंकों में जमा रकम को सुरक्षित माना जाता है। बड़े बैंक वैश्विक बैंकों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इससे आसानी से विदेशी व्यापार, निर्यात-आयात, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है। बड़े बैंक तकनीक, डिजिटल बैंकिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फिनटेक आदि में अधिक निवेश कर सकते हैं। बड़े बैंक सुगमता से तकनीक का उपयोग करते हैं, जिससे ग्राहक और आम जनता को लाभ पहुंचता है, लेनदेन सस्ता होता है, कारोबारियों को लाभ होता है, बैंकों की पहुंच ग्रामीण और पिछड़े इलाकों तक होती है, कारोबार बढ़ने से रोजगार सृजन होता है, आर्थिक विकास सभी तक पहुंचता है, योजनाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ती है। बड़े बैंक तेजी और पारदर्शिता से सभी योजनाओं को लागू कर सकते हैं।

बड़े बैंक रुपये के अंतरराष्ट्रीय उपयोग को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे डालर पर निर्भरता कम होगी और रुपये में मजबूती बनी रहेगी। बड़े बैंक मेक इन इंडिया की संकल्पना को साकार करने में मददगार बन सकते हैं। चीन के आइसीबीसी, बैंक आफ चाइना और चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक दुनिया के सबसे बड़े बैंक हैं, जो सरकार की औद्योगिक और विकास योजनाओं के अनुरूप ऋण प्रदान करते हैं। वहीं, अमेरिका में जेपी मार्गन, बैंक आफ अमेरिका, सिटीग्रुप, गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े बैंक हैं। यूरोप में एचएसबीसी, बीएनपी पारिबास, ड्यूश बैंक आदि प्रमुख हैं। ये वाणिज्यिक बैंक वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अहम भूमिका निभाते हैं।

ऐसे में यह कहा जा सकता है कि भारत में चीन जैसी दीर्घकालिक आधारभूत संरचना, अमेरिका जैसी नवाचार-उन्मुख स्टार्टअप और यूरोप जैसी एमएसएमई व हरित वित्त पोषण की आवश्यकता है। विश्वस्तरीय बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकते हैं। ये विकास को तेज करने में सक्षम होंगे। शिक्षा, उद्योग, शासन, सामाजिक सुधार के साथ ही बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत बनाने पर ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है।

संकट के संकेत

मानसून के विदा होते ही सूख जा रहीं प्रदेश की अधिकतर नदियां

बिहार की छोटी-छोटी नदियों के सूखने, सिकुड़ जाने या उनका अस्तित्व मिटते जाने का दुष्प्रभाव अंततः यहां के जनजीवन पर ही पड़ेगा। कुछ दुष्प्रभाव तो दिखने भी लगे हैं। भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है और नदियों से सिंचाई का पानी या तो नहीं मिल रहा है या अपेक्षाकृत कम मात्रा में मिल रहा है। इको सिस्टम बिगड़ रहा है सो अलग। इस समय सूबे की पांच दर्जन से अधिक नदियां संकट में हैं।

आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान' की ओर से रविवार को आयोजित संवाद में विशेषज्ञों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि मानव जीवन बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ा हो गया है। नदियों से पानी लगातार गायब हो रहा है। पानी आता भी है तो नदी में ठहरता नहीं है। महज 48 से 72 घंटे में ही समाप्त हो जाता है। यदि नदी में जलापूर्ति के स्रोत से पानी न आए तो पानी तीन दिन भी नहीं टिक पा रहा है। यह स्थिति विशेषज्ञों के लिए भी हैरान करने वाली है। इसके अलावा नदियों के मूल स्रोतों से पानी की आपूर्ति लगातार घटती जा रही है। गाद जमा होने से नदियां मृतप्राय होती जा रही हैं और अतिक्रमण के कारण सिकुड़ती जा रही हैं। इससे जलीय जीवों पर संकट गहरा गया है। खेतों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है और भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। मानसून के दौरान नदियों में पानी आता है, जिससे बड़े हिस्से में बाढ़ भी आती है। लेकिन मानसून समाप्त होते ही नदियां सूखने लगती हैं। अक्टूबर से ही नदियों के सूखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

05
दर्जन से अधिक नदियां सूख चुकीं या संकट में हैं सूबे में

इधर, एक नई समस्या भी सामने आ रही है। कई जिलों में प्रकृति की दोहरी मार देखने को मिल रही है। एक ही समय में जिले के एक हिस्से में अत्यधिक बारिश से जलभराव है, जबकि दूसरे हिस्से में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक ही जिले में बाढ़ और सुखाड़ दोनों की स्थिति बनी रहती है। जिले का एक भाग पानी में डूबा रहता है, तो दूसरा भाग पानी के लिए तरसता है।

पटना जिले के धनरुआ के कोल्हाचक में सूखी दरधा नदी। एक दशक पहले तक नदी में जनवरी महीने में भी पानी भरा रहता था। कभी जहानाबाद और नालंदा जिले के खेतों में इसके पानी से सिंचाई होती थी। • हिन्दुस्तान

कहां जाता है नदियों का पानी

विशेषज्ञों के अनुसार बिहार की नदियों का अधिकांश पानी बंगाल की खाड़ी में जाकर व्यर्थ हो जाता है। उत्तर और दक्षिण बिहार की सारी नदियों का पानी अंततः गंगा नदी में ही जाता है। गंगा नदी से होते हुए पानी बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। हर दिन पांच से दस लाख क्यूसेक पानी गंगा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इसी तरह बीते दिनों में बारिश की मात्रा कम होने से राज्य का भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। इससे नदियों के पानी का बड़ा हिस्सा भूजल को रिचार्ज करने में खत्म हो रहा है। भूजल इतना नीचे है कि उसे रिचार्ज करने पर भी उसका स्तर नीचे ही है। इससे नदियों में पानी कम होता है।

क्यों संकट में नदियां

जलवायु परिवर्तन, अनियमित व कम बारिश, जमीन का रिचार्ज न होना, जंगलों का बेतहाशा कटना, सिल्टेशन और नदियों के मूल स्रोत से पानी नहीं मिलने ये नदियां संकट में हैं। नदियों के असमय सूखने का बड़ा कारण जंगलों का बेतहाशा कटना है। जंगल होने से बारिश की बूंदों को पत्ते सहते हैं और पानी जमीन पर धीरे-धीरे जाता है। इससे सालों भर पानी का प्रवाह होता रहता है और जलस्तर बना रहता है। प्रतिकूल मौसम में भी नदियों में पानी की उपलब्धता बनी रहती थी। अब जंगल के अधिकांश भाग में बारिश का पानी सीधे जमीन पर जा रहा, जिससे पानी और गाद दोनों नदियों में पहुंच रही है।

ऐसे कम हो जाता है पानी

नेपाल में बारिश के बाद वहां से लगभग 300 स्रोतों से बिहार में पानी प्रवेश करता है। यह कई स्रोतों से होते हुए बड़ी नदियों में समाहित हो जाता है। इसके कारण कई छोटी नदियों में भी पानी आता है। लेकिन, इन स्रोतों से पानी की आपूर्ति बंद होने के बाद नदियां सूखने लगती हैं।

90 के दशक के बाद से बिगड़ने लगी स्थिति

सूबे में नदियों का संकट 90 के दशक के बाद बढ़ने लगा था। दरअसल, नदियों में पानी कम होने का सिलसिला 50-60 के दशक में शुरू हुआ। तब नदियों में पानी घटता था, उसकी कमी होती थी लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं होता था। रात में कुआं तक रिचार्ज हो जाता था। नदियां कलकल बहती थी। यहां तक कि 1967 के अकाल, 1972-73 और 1992-93 के संकट के समय भी नदियों या अन्य स्रोतों में पानी की ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन 1990 के बाद सूबे में यह संकट बढ़ता चला गया। आज स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है।

Hindustan Page No-8

स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत 'समुद्र प्रताप' रिमोट कंट्रोल गन से लैस होगा

जलावतरण आज

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के पोत 'समुद्र प्रताप' का जलावतरण करेंगे। यह पोत आधुनिक हथियारों और रिमोट कंट्रोल गन से लैस होगा और यह आईसीजी का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत भी है।

यह पोत तेल रिसाव का पता लगाने के लिए उन्नत प्रणालियों से भी लैस है, जिससे विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के भीतर और उसके बाहर व्यापक प्रदूषण रोधी अभियान चलाने में मदद मिलेगी। इस पोत में डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम (डीपी-1) लगा है। समुद्र प्रताप के शामिल होने से भारतीय तटरक्षक बल की समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इसके निर्माण ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को भी मजबूत किया है।

कई देश में मौजूद है व्यवस्था : अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, स्वीडन, नॉर्वे, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, जैसे देशों में ऐसे प्रदूषण नियंत्रण जहाज से तेल रिसाव को साफ करना और समुद्र कचरा प्रबंधन की व्यवस्था पहले से मौजूद है।

समुद्री क्षेत्र में गैर-पारंपरिक खतरे बढ़ रहे: राजनाथ सिंह

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारतीय शिपयार्डों की अहम भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि समुद्री क्षेत्र में पारंपरिक चुनौतियों के साथ गैर-पारंपरिक खतरे भी लगातार बढ़ रहे हैं।

उन्होंने यह बातें प्रदूषण नियंत्रण पोत (पीसीवी) 'समुद्र प्रताप' के भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) में शामिल होने की पूर्व संध्या पर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) के दौरे पर कहीं। राजनाथ ने कहा कि जीएसएल और अन्य भारतीय शिपयार्डों द्वारा भारतीय नौसेना और आईसीजी के लिए निर्मित पोत भारत की संप्रभुता के तैरते प्रतीक हैं। ये खुले समुद्र में हमारी उपस्थिति, क्षमता और दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनाथ ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को रणनीतिक जरूरत बताया व जीएसएल की सराहना कर कहा कि वे इस जरूरत को वास्तविकता में बदल रही हैं।

Hindustan Page No-6

Useful For Mains

अहंकार मनुष्य के भीतर पनपने वाला शत्रु, इसको परास्त करें

जनसत्ता धर्मदीक्षा

अहंकार स्वयं को दूसरों और ईश्वर से भी श्रेष्ठ समझना है, जो सभी पापों की जड़ है। यह स्वयं की उपलब्धियों, अपने करीबी लोगों की उपलब्धियों, या व्यापक रूप से प्रशंसित गुणों या संपत्तियों से प्राप्त होने वाला गहरा सुख या संतोष है। अहंकार हमारी उपलब्धियों का बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया भाव है, गर्व और अत्यधिक आत्मसम्मान की अवस्था है।

मनुष्य को अहंकारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने वास्तविक स्वरूप से ऊपर दिखना चाहता है। अहंकार- प्रधान जीवन में हम अपनी मूलभूत ऊर्जा अपने अहंकार से प्राप्त करते हैं, जबकि ईश्वर-आधारित जीवन में हम अपनी ऊर्जा अपने से परे किसी स्रोत, यानी ईश्वर से प्राप्त करते हैं। अहंकार-प्रधान जीवन में हम आसानी से और अक्सर निराश, क्रोधित और अवसादग्रस्त हो जाते हैं। ईश्वर-आधारित जीवन में जीवन के उतार-चढ़ाव हमें इतना गहराई से प्रभावित नहीं करते। हम अपने अहंकार के उतार-चढ़ाव से परे जीवन का अर्थ खोज लेते हैं। अहंकार भी मनुष्य के अंदर पनपने वाला एक ऐसा ही शत्रु है। अहंकार के बीज को अपने हृदय में पनपने का अवसर ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि अहंकार का वृक्ष फल वाले वृक्षों के स्थान पर विषवृक्ष सिद्ध होता है, जो व्यक्ति को अत्यंत कष्ट और हानि पहुंचाता है।

अहंकार से दूसरे व्यक्ति तो बाद में प्रभावित होते हैं, लेकिन सबसे पहले अहंकार से पीड़ित मनुष्य ही इससे प्रभावित होता है। अहंकार व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक परिवेश पर असर डालता है। वह अर्थ के मामले में भी पिछड़ जाता है। अहंकार विनय को समाप्त कर देता है, जबकि अक्सर सामाजिक स्तर पर विनय, धैर्य, मधुर वाणी और ईमानदारी जैसे भाव ही व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर ऊपर उठने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति अध्यात्म की ओर मुड़ ही नहीं पाता। वह जीवन के उन सुंदर क्षणों से अपरिचित रहता है जो केवल अध्यात्म के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अहंकार ने रावण के साम्राज्य तक को नष्ट कर दिया था। अहंकार व्यक्ति की सोचने और कर्म करने की क्षमता पर भी प्रतिकूल असर डालता है। जहां विनयपूर्ण व्यवहार और सबका आदर करने वाला व्यक्ति सहज ही सबका प्रिय बन जाता है। अक्सर व्यक्ति सफल और कामयाब होने पर अहं के नशे में डूब जाता है। ऐसे में सफलता हासिल करने के बाद भी यदि व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा रहे तो वह अहंकार से दूर रह सकता है।

श्रीकृष्ण की विनम्रता और सद्गुणों से सभी परिचित हैं। श्रीकृष्ण ने राजसूय यज्ञ में सभी ऋषियों और विद्वानों के चरणों को धोने का कार्य अपने हाथों से किया था। ऐसे ही सद्गुण व्यक्ति के लिए अनिवार्य है ताकि वह अहंकार से दूर रहे। अहंकार एक ऐसा शत्रु है जो अन्य शत्रुओं को जन्म देता है और व्यक्ति की जिंदगी को नर्क बना देता है। अहंकार में मदमस्त व्यक्ति क्रोध, लोभ, और ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति कालांतर में कई मनोविकारों का शिकार हो जाता है। अहंकार जब चरम पर होता है तो वह किसी भी व्यक्ति में यह विश्वास दिलाता है कि वही सब कुछ नियंत्रित कर रहा हैऔर सब कुछ उसके ही हाथ में है। वास्तव में ऐसा व्यक्ति एक झूठी वास्तविकता में जीता है।

सार संसार

इन तीन तरीकों से अहंकार को विनम्रता से बदलें

1. विनम्रता या निस्वार्थता का अर्थ है यह स्वीकार करना कि व्यक्ति के कौशल, प्रतिभा और अच्छे गुण ईश्वर की देन हैं। वह अपने महत्त्व को विनम्रतापूर्वक समझता है। सभी को इस क्षेत्र में आत्म सुधार की आवश्यकता है क्योंकि यह मानवीय स्वभाव का एक हिस्सा है।
2. विनम्र रहें, यह समझते हुए कि आपको ईश्वर और अन्य लोगों की आवश्यकता है। विनम्रता के लिए प्रार्थना करें। खुद को वंचित रखें। धैर्य रखें। घमंड न करें, दिखावा न करें, श्रेष्ठता का भाव न दिखाएं। दयालु और परोपकारी बनें। दूसरों की सेवा करें।
3. नम्रता का अभ्यास अहंकार के पाप पर विजय दिलाता है। अहंकार दुर्गुण है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह ईश्वर से है, और हम जो कुछ भी करते हैं वह उनके दिए गए वरदानों से प्रेरित है, तो हम स्वयं से बाहर निकल जाते हैं।

दुष्प्रभाव क्या हैं?

- अहंकार से भरा आत्म प्रेम सीधे तौर पर ईश्वर के प्रति समर्पण की आवश्यकता के विपरीत है।
- हर पाप में अहंकार का कुछ अंश होता है, जो इसे सभी पापों में सबसे बड़ा पाप बनाता है।
- वह श्रेष्ठता, स्वार्थ, मनमानी, आत्म-भ्रम और यहां तक कि आत्म-दया के रूप में व्यक्त होता है।
- अहंकार इस बात से इनकार करता है कि हमारी सभी आशीष ईश्वर से आती हैं।
- वह सभी अच्छे कार्यों और सद्गुणों को नष्ट कर सकता है।

कैसे पहचानें

अवज्ञा : अधिकार का पालन करने में विफलता या इनकार।

घमंड करना : अत्यधिक गर्व दिखाना।

पाखंड : अपने मानकों के अनुरूप न होना।

विवाद : झगड़े करना या तीखी बहस करना।

हठधर्मिता : हठ का भाव।

असामंजस्य : सामंजस्य की कमी।

समानुभूति की संवेदना

संध्या राजपुरोहित

समकालीन समाज तेजी से बदल रहा है। हर दिन अखबारों और डिजिटल माध्यमों में पीड़ा, असमानता और संघर्ष की खबरें आम हो गई हैं। आदिवासी अंचलों में विस्थापन, शहरों की ओर बढ़ता पलायन, शिक्षा से बाहर होते बच्चे और महिलाओं के साथ होती हिंसा- ये अब केवल घटनाएं नहीं, बल्कि आंकड़ों में दर्ज सच्चाइयां हैं। इन पर हम दुख व्यक्त करते हैं, सहानुभूति जताते हैं, लेकिन हमारा सामाजिक आचरण अक्सर वहीं ठहर जाता है।

किसी के दुख को देखकर करुणा का भाव जागना समाज को असंवेदनशील होने से बचाता है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब यह भावना केवल शब्दों, बयानों और औपचारिक प्रतिक्रियाओं तक सीमित रह जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित सामाजिक और आर्थिक रपटें बताती हैं कि असमानता और वंचना आज भी व्यापक है, फिर भी अधिकांश मामलों में हमारी भूमिका केवल चिंता व्यक्त करने तक सिमट जाती है। असल में सहानुभूति हमें भावनात्मक संतोष देती है, पर व्यावहारिक जिम्मेदारी का बोध नहीं कराती।

आदिवासी समाज इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6 फीसद हिस्सा अनुसूचित जनजातियों का है, लेकिन विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले लोगों में उनकी हिस्सेदारी अनुपात से कहीं अधिक रही है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार बड़े बांधों, खनन और औद्योगिक परियोजनाओं से प्रभावित लोगों में लगभग चालीस फीसद तक आदिवासी समुदायों से आते हैं। यह तथ्य केवल विस्थापन का नहीं, बल्कि संस्कृति, आजीविका और सामाजिक पहचान के टूटने का भी संकेत देता है। सहानुभूति के रूप में मुआवजे और पुनर्वास की योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन समानुभूति तभी होगी, जब नीति निर्माण की प्रक्रिया में प्रभावित समुदायों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित की जाए और विकास को उनके जीवन-संदर्भ से जोड़कर देखा जाए। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी यही अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। यूनिसेफ और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जैसी संस्थाओं की रपटें बताती हैं कि आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर अब भी चिंता का विषय है, विशेषकर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में। सहानुभूति के तौर पर छात्रवृत्तियां, मध्याह्न भोजन और योजनाएं मौजूद हैं, पर समानुभूति तब सामने आती है जब शिक्षा व्यवस्था यह स्वीकार करती है कि भाषा, गरीबी और पारिवारिक जिम्मेदारियां सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। जब शिक्षक और व्यवस्था बच्चे की पृष्ठभूमि को समझकर अपनी पद्धति में बदलाव करते हैं, तभी शिक्षा वास्तव में समावेशी बनती है।

दुनिया मेरे आगे

> **डिजिटल युग ने संवेदनाओं को भी एक नए रूप में ढाल दिया है। सोशल मीडिया पर किसी मुद्दे से जुड़े आंकड़े, तस्वीरें और वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में उनका प्रभाव सीमित रह जाता है। यह तथाकथित डिजिटल सहानुभूति हमें प्रतिक्रिया तो देती है, पर सहभागिता नहीं सिखाती।**

ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर बढ़ता पलायन भी हमारे सामाजिक आचरण की परीक्षा लेता है। करोड़ों लोग रोजगार की तलाश में अपने गांव छोड़कर शहरों में अस्थायी या असुरक्षित परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। शहरी अर्थव्यवस्था इन श्रमिकों पर निर्भर है, फिर भी सामाजिक व्यवहार में वे अक्सर अदृश्य रहते हैं। हम उनके श्रम का लाभ उठाते हैं, पर उनके आवास, स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा को लेकर उदासीन बने रहते हैं। यह उदासीनता सहानुभूति की सीमा को दर्शाती है, जहां समस्या को देखा तो जाता है, पर उसे अपना नहीं माना जाता।

डिजिटल युग ने संवेदनाओं को भी एक नए रूप में ढाल दिया है। सोशल मीडिया पर किसी मुद्दे से जुड़े आंकड़े, तस्वीरें और वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में उनका प्रभाव सीमित रह जाता है। यह तथाकथित डिजिटल सहानुभूति हमें प्रतिक्रिया तो देती है, पर सहभागिता नहीं सिखाती। असल में केवल आर्थिक या तकनीकी प्रगति पर्याप्त नहीं, जब तक सामाजिक और मानवीय दृष्टि उसके साथ न चले। सामाजिक आचरण तब बदलता है, जब संवेदना औपचारिकता से निकलकर व्यवहार में उतरती है। जब नीति निर्माण में आंकड़ों के साथ मानवीय अनुभवों को महत्त्व दिया जाता है, जब योजनाएं बनाते समय जमीनी सच्चाइयों को समझा जाता है, तब सहानुभूति समानुभूति में बदलती है।

सोमनाथ : अटूट आस्था के 1000 वर्ष

वर्ष 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए बहुत महत्त्व रखता है क्योंकि इस महान तीर्थ पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनवरी 1026 में गजनी के महमूद ने इस मंदिर पर बड़ा आक्रमण किया था, इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था।

नरेंद्र मोदी

सोमनाथ... ये शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में, प्रभास पाटन नाम की जगह पर स्थित सोमनाथ, भारत की आत्मा का शाश्वत प्रस्तुतिकरण है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है। ज्योतिर्लिंगों का वर्णन इस पंक्ति से शुरू होता है...'सौराष्ट्रे सोमनाथं च...यानि ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का उल्लेख आता है। ये इस पवित्र धाम की सभ्यतागत और आध्यात्मिक महत्ता का प्रतीक है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है:

'सोमलिङ्गं नरो दृष्ट्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते।
लभते फलं मनोवाञ्छितं मृतः स्वर्गं समाश्रयेत्॥'

अर्थात सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मन में जो भी पुण्य कामनाएं होती हैं, वो पूरी होती हैं और मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग को प्राप्त होती है।

दुर्भाग्यवश, यही सोमनाथ, जो करोड़ों लोगों की श्रद्धा और प्रार्थनाओं का केंद्र था, विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बना, जिनका उद्देश्य विध्वंस था। वर्ष 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए बहुत महत्त्व रखता है क्योंकि इस महान तीर्थ पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनवरी 1026 में गजनी के महमूद ने इस मंदिर पर बड़ा आक्रमण किया था, इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। यह आक्रमण आस्था और सभ्यता के एक महान प्रतीक को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया एक हिंसक और बर्बर प्रयास था।

सोमनाथ हमला मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में शामिल है। फिर भी, एक हजार वर्ष बाद आज भी यह मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है। साल 1026 के बाद समय-समय पर इस मंदिर को उसके पूरे वैभव के साथ पुनःनिर्मित करने के प्रयास जारी रहे। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1951 में आकार ले सका। संयोग से 2026 का यही वर्ष सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का भी वर्ष है। 11 मई 1951 को इस मंदिर का पुनर्निर्माण सम्पन्न हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति डा राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में हुआ वो समारोह ऐतिहासिक था, जब मंदिर के द्वार दर्शन के लिए खोले गए थे।

1026 में एक हजार वर्ष पहले सोमनाथ पर हुए पहले आक्रमण, वहां के लोगों के साथ की गई क्रूरता और विध्वंस का वर्णन अनेक ऐतिहासिक स्रोतों में विस्तार से मिलता है। जब इन्हें पढ़ा जाता है तो हृदय कांप उठता है। हर पंक्ति में क्रूरता के निशान मिलते हैं, ये ऐसा दुःख है जिसकी पीड़ा इतने समय बाद भी महसूस होती है। हम कल्पना कर सकते हैं कि इसका उस दौर में भारत पर और लोगों के मनोबल पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा। सोमनाथ मंदिर का आध्यात्मिक महत्त्व बहुत ज्यादा था। ये बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींचता था। ये एक ऐसे समाज की प्रेरणा था जिसकी आर्थिक क्षमता भी बहुत सशक्त थी। हमारे समुद्री व्यापारी और नाविक इसके वैभव की कथाएं दूर-दूर तक ले जाते थे।

सोमनाथ पर हमले और फिर गुलामी के लंबे कालखंड के बावजूद आज मैं पूरे विश्वास के साथ और गर्व से ये कहना चाहता हूं कि सोमनाथ की गाथा विध्वंस की कहानी नहीं है। ये पिछले 1000 साल से चली आ रही भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है, ये हम भारत के लोगों की अटूट आस्था की गाथा है।

साल1026 में शुरू हुई मध्यकालीन बर्बरता ने आगे चलकर दूसरों को भी बार-बार सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। यह हमारे लोगों और हमारी संस्कृति को गुलाम बनाने का प्रयास था। लेकिन हर बार जब मंदिर पर आक्रमण हुआ, तब हमारे पास ऐसे महान पुरुष और महिलाएं भी थीं जिन्होंने उसकी रक्षा के लिए खड़े होकर सर्वोच्च बलिदान दिया। और हर बार, पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारी महान सभ्यता के लोगों ने खुद को संभाला, मंदिर को फिर से खड़ा किया और उसे पुनः जीवंत किया।

महमूद गजनवी लूटकर चला गया, लेकिन सोमनाथ के प्रति हमारी भावना

को हमसे छीन नहीं सका। सोमनाथ से जुड़ी हमारी आस्था, हमारा विश्वास और प्रबल हुआ। उसकी आत्मा लाखों श्रद्धालुओं की भीतर सांस लेती रही। साल 1026 के हजार साल बाद आज 2026 में भी सोमनाथ मंदिर दुनिया को संदेश दे रहा है कि मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, जबकि सोमनाथ आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। वो आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत है, वो आज भी हमारी शक्ति का पुंज है।

ये हमारा सौभाग्य है कि हमने उस धरती पर जीवन पाया है, जिसने देवी अहिल्याबाई होलकर जैसी महान विभूति को जन्म दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने का पुण्य प्रयास किया कि श्रद्धालु सोमनाथ में पूजा कर सकें। 1890 के दशक में स्वामी विवेकानंद भी सोमनाथ आए थे, वो अनुभव उन्हें भीतर तक आंदोलित कर गया। 1897 में चेन्नई में दिए गए एक व्याख्यान के दौरान उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की। उन्होंने कहा, 'दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर और गुजरात के सोमनाथ जैसे मंदिर आपको ज्ञान के अनगिनत पाठ सिखाएंगे। ये आपको किसी भी संख्या में पढ़ी गई पुस्तकों से अधिक हमारी सभ्यता की गहरी समझ देंगे। इन मंदिरों पर सैकड़ों आक्रमणों के निशान हैं, और सैकड़ों बार इनका पुनर्जागरण हुआ है। ये बार-बार नष्ट किए गए, और हर बार अपने ही खंडहरों से फिर खड़े हुए। पहले की तरह सशक्त। पहले की तरह जीवंत। यही राष्ट्रीय मन है, यही राष्ट्रीय जीवन धारा है। इसका अनुसरण आपको गौरव से भर देता है। इसको छोड़ देने का मतलब है, मृत्यु। इससे अलग हो जाने पर विनाश ही होगा।'

> **ये सर्वविदित है कि आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पवित्र दायित्व सरदार वल्लभभाई पटेल के सक्षम हाथों में आया। उन्होंने आगे बढ़कर इस दायित्व के लिए कदम बढ़ाया। 1947 में दिवाली के समय उनकी सोमनाथ यात्रा हुई। उस यात्रा के अनुभव ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया, उसी समय उन्होंने घोषणा की कि यहीं सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। अंततः 11 मई 1951 को सोमनाथ में भव्य मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। महान सरदार साहब इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए जीवित नहीं थे, लेकिन उनका सपना राष्ट्र के सामने साकार होकर भव्य रूप में उपस्थित था।**

ये सर्वविदित है कि आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पवित्र दायित्व सरदार वल्लभभाई पटेल के सक्षम हाथों में आया। उन्होंने आगे बढ़कर इस दायित्व के लिए कदम बढ़ाया। 1947 में दिवाली के समय उनकी सोमनाथ यात्रा हुई। उस यात्रा के अनुभव ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया, उसी समय उन्होंने घोषणा की कि यहीं सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। अंततः 11 मई 1951 को सोमनाथ में भव्य मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। उस अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति डा राजेंद्र प्रसाद उपस्थित थे। महान सरदार साहब इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए जीवित नहीं थे, लेकिन उनका सपना राष्ट्र के सामने साकार होकर भव्य रूप में उपस्थित था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बनें। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी, लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे, और फिर जो हुआ, उसने एक नया इतिहास रच दिया।

सोमनाथ मंदिर का कोई भी उल्लेख केएम मुंशी जी के योगदानों को याद किए बिना अधूरा है। उन्होंने उस समय सरदार पटेल का प्रभावी रूप से समर्थन किया था। सोमनाथ पर उनका कार्य, विशेष रूप से उनकी पुस्तक 'सोमनाथ, द श्राइन इटरनल', अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। जैसा कि मुंशी जी की पुस्तक के शीर्षक से स्पष्ट होता है, हम एक ऐसी सभ्यता हैं जो आत्मा और विचारों की अमरता में अटूट विश्वास रखती है। हम विश्वास करते हैं- नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। सोमनाथ का भौतिक ढांचा नष्ट हो गया, लेकिन उसकी चेतना अमर रही।

इन्हीं विचारों ने हमें हर कालखंड में, हर परिस्थिति में फिर से उठ खड़े होने, मजबूत बनने और आगे बढ़ने का सामर्थ्य दिया है। इन्हीं मूल्यों और हमारे लोगों के संकल्प की वजह से आज भारत पर दुनिया की नजर है। दुनिया भारत को आशा और विश्वास की दृष्टि से देख रही है। वह हमारे सृजनशील (इनोवेटिव) युवाओं में निवेश करना चाहती है। हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारा संगीत और हमारे अनेक पर्व आज वैश्विक पहचान बना रहे हैं। योग और आयुर्वेद जैसे विषय पूरी दुनिया में प्रभाव डाल रहे हैं। ये स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दे रहे हैं। आज कई वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। अनादि काल से सोमनाथ जीवन के हर क्षेत्र के लोगों को जोड़ता आया है। सदियों पहले जैन परंपरा के आदरणीय मुनि कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य यहां आए थे और कहा जाता है कि प्रार्थना के बाद उन्होंने कहा,

'भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याः क्षयमुपगता यस्य।'

अर्थात उस परम तत्त्व को नमन जिसमें सांसारिक बंधनों के बीज नष्ट हो चुके हैं। जिसमें राग और सभी विकार शांत हो गए हैं। आज भी दादा सोमनाथ के दर्शन से ऐसी ही अनुभूति होती है। मन में एक ठहराव आ जाता है, आत्मा को अंदर तक कुछ स्पर्श करता है, जो अलौकिक है, अव्यक्त है। वर्ष 1026 के पहले आक्रमण के एक हजार वर्ष बाद 2026 में भी सोमनाथ का समुद्र उसी तीव्रता से गर्जना करता है और तट को स्पर्श करती लहरें उसकी पूरी गाथा सुनाती हैं। उन लहरों की तरह सोमनाथ बार-बार उठता रहा है। अतीत के आक्रमणकारी आज समय की धूल बन चुके हैं। उनका नाम अब विनाश के प्रतीक के तौर पर लिया जाता है। इतिहास के पन्नों में वे केवल फुटनोट हैं, जबकि सोमनाथ आज भी अपनी आशा बिखेरता हुआ प्रकाशमान खड़ा है। सोमनाथ हमें ये बताता है कि घृणा और कट्टरता में विनाश की विकृत ताकत हो सकती है, लेकिन आस्था में सृजन की शक्ति होती है। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सोमनाथ आज भी आशा का अनंत नाद है। ये वो स्वर है, जो टूटने के बाद भी उठने की प्रेरणा देता है।

अगर हजार साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है, तो हम हजार साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। आइए, इसी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक नए संकल्प के साथ, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए। एक ऐसा भारत, जिसका सभ्यतागत ज्ञान हमें विश्व कल्याण के लिए प्रयास करते रहने की प्रेरणा देता है।

जय सोमनाथ!

(लेखक भारत के प्रधानमंत्री हैं)

स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी और संसाधनों का मेल जरूरी

इंदौर में हाल ही में पानी के खराब होने की घटना ने लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया है। इसकी इंसानी कीमत बहुत ज्यादा है। परिवारों को ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती और कोई भी तकनीकी वजह या संस्थागत बचाव इस सच्चाई को कम नहीं कर सकता। तुरंत राहत, मेडिकल मदद और सही मुआवजा जरूरी है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन यहीं रुकना एक बड़ी गलती होगी। अगर इंदौर का जवाब सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट और गलती ढूंढने तक ही सीमित रहा, तो भारत में कहीं और भी वही दुखद घटना दोहराने का खतरा है। यह घटना जो दिखाती है वह कोई एक बार की नाकामी नहीं है, बल्कि शहरी पानी और सफाई सिस्टम को चलाने, स्टाफ रखने, फाइनेंस करने और जिम्मेदार ठहराने के तरीके में एक संरचनात्मक कमजोरी है।

हितेष वैद्य
पूर्व निदेशक, एनआइयूए

बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में नाकामियों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, जब तक कि उनके पास इसके लिए साफ तौर पर आदेश न हों। जरूरी फंड और पेशेवर कर्मी न हों। इसके लिए शहरी सुधार 3.0 पर अमल जरूरी है।

भारत को अब शहरी सुधार 3.0 की जरूरत है। यह सुधार का ऐसा एजेंडा है जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने से आगे बढ़कर संस्थागत मजबूती की ओर ले जा सकता है। इसके मूल में एक सीधा सिद्धांत है। शहरों को नाकामियों के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए जब तक कि उन्हें रोकने के लिए साफ तौर पर आदेश न दिए जाएं, उनके पास सही फंड न हो, और प्रोफेशनल स्टाफ न हो। भारत के शहरी प्रोग्राम इन्फ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी में तेजी लाने में असरदार रहे हैं, लेकिन शहरों में टिकाऊ संस्थागत क्षमता बनाने में बहुत कम सफल रहे हैं। इसके लिए पांच संरचनात्मक बदलावों की जरूरत है।

स्पष्ट आदेश और जवाबदेही: पीने के पानी की सुरक्षा जैसी जरूरी सेवाओं के लिए साफ तौर पर एक संस्था की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। जवाबदेही तभी काम करती है, जब जिम्मेदारी साफ हो।

जिम्मेदारियों और संसाधनों का मेल जरूरी: कानूनी जिम्मेदारियां उपलब्ध वित्त और पेशेवर कर्मचारी के अनुपात से होना चाहिए। इस मेल के बिना विकेंद्रीकरण सिर्फ कहने का विषय रह जाता है। पानी की आपूर्ति, सीवरेज, मल का प्रबंधन, और पब्लिक हेल्थ के कामों को अलग करने के बजाय एकीकृत किया जाना चाहिए।

पब्लिक यूटिलिटीज सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं: पानी और सैनिटेशन सिस्टम को प्रोजेक्ट यूनिट के बजाय पब्लिक हेल्थ यूटिलिटीज की तरह माना जाना चाहिए। इसका मतलब है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सर्विस-लेवल बेंचमार्क, आडिटेड परफार्मेंस, पालिसी, रेगुलेशन और आपरेशन के बीच सटीक अलगाव। पानी का क्वालिटी मैनेजमेंट और पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर साफ तौर पर बताए जाने चाहिए, टेस्ट किए जाने चाहिए।

सार्वजनिक स्वास्थ्य हो पहली प्राथमिकता: बीच-बीच में पानी की सप्लाई बंद होना सिर्फ एक अस्थायी असुविधा नहीं है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक जोखिम है। शहरों को दबावयुक्त, लगातार आपूर्ति वाले सिस्टम में बदलने में मदद मिलनी चाहिए, जिसे लीकेज कंट्रोल, रियल-टाइम पानी की क्वालिटी की निगरानी, और पानी, सैनिटेशन, ड्रेनेज और कचरा प्रबंधन में इंटीग्रेटेड प्लानिंग का सपोर्ट हो।

मिशन और रैंकिंग से परे संस्थागत निरंतरता: शहर मिशन से ज्यादा समय तक चलते हैं। सुधारों को रैंकिंग और शार्ट-टर्म इंसेंटिव पर कम और ऐसे संस्थान बनाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो राजनीतिक और प्रशासनिक चक्रों में बने रहें। पानी की सप्लाई, सैनिटेशन और कचरा प्रबंधन सिर्फ इंजीनियरिंग का काम नहीं हैं, वे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं। जब वे फेल होते हैं, तो इसके नतीजे बैलेंस शीट या रैंकिंग में नहीं, बल्कि जान गंवाने वालों की संख्या में गिने जाते हैं। इंदौर की त्रासदी सिर्फ एक शहर के लिए नहीं, बल्कि भारत के शहरी सुधार एजेंडे के लिए एक टर्निंग पाइंट होनी चाहिए।

Dainik Jagaran Page No-7

पानी को अगर हम लोकतंत्र की तरह समझें, तो इसका भविष्य सुरक्षित रहेगा, क्योंकि पानी पर पहला अधिकार समाज का है, नाकि बाजार का। **राजेंद्र सिंह,** जल पुरुष

Dainik Jagaran Page -7

स्वच्छ पेयजल: हमारा अधिकार

हर साल चार लाख मौतें, नहीं टूट रही नींद

अरविंद पांडेय • जागरण

नई दिल्ली : देश में शुद्ध पेजयल न मुहैया होने से हर साल चार लाख लोगों की मौत डायरिया से हो रही है, साथ ही करीब एक करोड़ लोग दिव्यांगता या दूसरी संक्रमित बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इसके बावजूद राज्य सरकारों की तंद्रा नहीं टूट रही। लगातार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीत रहे इंदौर में अशुद्ध पेयजल से हुई मौतों ने थोड़ा झकझोरा तो है लेकिन हकीकत यह है कि पेयजल आपूर्ति अभी तक राज्य सरकारों की प्राथमिकता में आ नहीं पाई है। केवल आंकड़े देख लीजिए तो पता चल जाएगा। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति व सीवर लाइन के लिए स्वीकृत 1.93 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं में से केवल 44 हजार करोड़ के काम पूरे हो पाए हैं जबकि अमृत (अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन) की अवधि इसी साल मार्च में खत्म हो रही है।

इंदौर तो एक झांकी है। सच्चाई यह है के सीवर और पेयजल लाइन की खराब प्लानिंग व डिजायन, जल संचयन के अपर्याप्त प्रबंधन और शुद्धीकरण के लिए इंतजाम व निगरानी के अभाव ने ऐसी स्थिति खड़ी कर दी है कि कोई भी शहर ऐसा नहीं जहां कुछ आबादी तक अशुद्ध जल न पहुंचता हो। शासन-प्रशासन और जन प्रतिनिधियों के कान में घंटी तब बजती है, जब मौतें होती हैं। इंदौर में भी यही हुआ है।

इंदौर का विरोधाभास देखिए- इंदौर शहर के पास के एक गांव रालामंडल में ग्रामीण जल जीवन मिशन के तहत सभी काम पूरे दिखाए जा रहे हैं। इंटरनेट पर आंकड़ा बताता है कि इस गांव में पेयजल की शुद्धता की आखिरी जांच 17 दिसंबर 2025 को हुई और सब कुछ दुरुस्त पाया गया। लेकिन शहर में मौत से पहले की जो अनदेखी हुई और मंत्री स्तर से संवेदनहीनता दिखी, वह कुछ और बयां कर रहा है। बहुत संभव है के कागजी घोड़े ज्यादा दौड़ लगा रहे हैं। इस मिशन के तहत आबादी के हिसाब से फंडिग पैटर्न है जिसमें केंद्र और राज्यों की भागीदारी होती है। संभवतः कई राज्यों में फंड की कमी भी आड़े आ रही हो, लेकिन यह सच है रेवड़ी संस्_ति में कोई राज्य पीछे नहीं है।

शुद्ध जल की समस्या को दूर करने के लिए पहली बार केंद्र की ओर से दो मिशन शुरू किए गए, इनमें एक शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेजयल और सीवरेज प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए अमृत मिशन है, जबकि दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर तक शुद्ध नल जल मुहैया कराने के लिए जल जीवन मिशन है। पर इस मूलभूत जरूरत के लिए राज्य सरकारों में सक्रियता की कमी रही। शुद्ध पेजयल मुहैया कराने से जुड़ी परियोजनाओं पर राज्यों के इस सुस्त रवैये और केंद्र की कमजोर निगरानी पर हाल ही में संसदीय समिति ने भी सवाल खड़े किए हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप करने को कहा है।

अमृत मिशन 1.0 में जहां 32 पुराने जल शोधन संयंत्रों के उन्नयन से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, वहीं अमृत मिशन 2.0 में 132 नए जल शोधन संयंत्रों को लगाने की परियोजना स्वीकृत की गई, लेकिन राज्यों का सुस्त रवैया कुछ इस तरह है कि इनमें से सिर्फ चार परियोजनाएं ही अब तक पूरी हो पाई हैं। इनमें सबसे अधिक 43 जल शोधन संयंत्रों को लगाने के प्रस्ताव मध्य प्रदेश में स्वीकृत किए गए हैं, जबकि अभी तक एक भी इनमें से पूरा नहीं हो पाया है। इन मिशनों के तहत नगरीय निकायों और गांव पंचायतों को भी हर घर शुद्ध जल मुहैया कराने के लिए एक तंत्र विकसित करने के लिए कहा गया था ताकि इन परियोजनाओं को आगे भी बेहतर ढंग से संचालित और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए विस्तार दिया जा सके। इनमें पानी पर कर लगाने व उसे वसूलने और पानी की 24 घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे कदम उठाने के लिए कहा गया था। लेकिन इन पर भी कुछ नगरीय निकायों को छोड़ दें तो कहीं कोई काम नहीं हुआ।

प्रति व्यक्ति 1,700 घन मीटर से कम वार्षिक जल उपलब्धता है तो माना जाता है जल संकट: वैश्विक मानक को देखे तो यदि प्रति व्यक्ति 1,700 घन मीटर से कम वार्षिक जल उपलब्धता है तो उसे जल संकट माना जाएगा। वर्तमान में देश में प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता 1,341 घन मीटर हो गई है, जबकि 2021 में यह आंकड़ा 1,487 घन मीटर था। यानी देश में जल संकट बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 20 सबसे अधिक जल संकटग्रस्त शहरों में पांच भारत से हैं। इनमें दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद शामिल हैं। मंत्रालय की घर-घर जल पहुंचाने की पहल को इस संकट से निपटने की कोशिश माना जा रहा है। मौजूदा समय में देश में पीने के पानी का ठीक से प्रबंधन न होने से बड़ी संख्या में पानी खराब हो रहा है। यह स्थिति तब है, जब दुनिया की करीब 17 प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है, वहीं मीठे पानी की उपलब्धता यानी उसके स्रोत सिर्फ चार प्रतिशत ही मौजूद हैं।

अमृत मिशन 1.0

अवधि- 2015-16 से 2020-21 तक, कुल स्वीकृत परियोजनाएं- 6008, कुल लागत- 83,463 करोड़ रुपये।

79 हजार करोड़ के काम पूरे हो चुके हैं। करीब चार हजार करोड़ के काम अभी लंबित हैं। वहीं केंद्र अब तक राज्यों को 34,900 करोड़ की वित्तीय सहायता दे चुका है। इन परियोजनाओं में 43 हजार करोड़ की 1403 जलपूर्ति परियोजनाएं थीं, जबकि 34 हजार करोड़ की 890 सीवरेज और सेप्टेज परियोजनाएं शामिल थीं।

अमृत मिशन 1.0 में स्वीकृत प्रोजेक्ट और राशि

राज्य	कुल परियोजनाएं	लागत राशि (करोड़ रुपये में)
बिहार	40	2,543
छत्तीसगढ	114	2,427
दिल्ली	19	658
गुजरात	266	4,885
हरियाणा	103	2,877
हिमाचल प्रदेश	49	213
जम्मू-कश्मीर	53	347
झारखंड	24	1,585
मध्य प्रदेश	84	6,410
पंजाब	120	2,746
उत्तर प्रदेश	328	11,590
उत्तराखंड	106	575
बंगाल	56	3,953

अमृत मिशन-2.0

अवधि- 2021-22 से 2025-26, कुल अनुमानित लागत 2.77 लाख करोड़ रुपये, हालांकि स्वीकृत परियोजनाएं- कुल 8791, लागत 1.93 लाख करोड़ रुपये। अब तक 44 हजार करोड़ का काम ही पूरा हो पाया, जबकि 35 हजार करोड़ रुपये अब तक खर्च हुए हैं।

अमृत मिशन का फंडिग पैटर्न

10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को कुल परियोजना लागत का एक-तिहाई केंद्र सरकार देती है, जबकि एक लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में परियोजना लागत की 50 प्रतिशत केंद्रीय सहायता दी जाती है।

जल जीवन मिशन का फंडिग पैटर्न

हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों को परियोजना लागत का 90 प्रतिशत केंद्र देता है, जबकि 10 प्रतिशत राज्य देते हैं, वहीं बाकी राज्यों में परियोजनाओं का आधा-आधा पैसा केंद्र और राज्य दोनों वहन करते हैं।

स्वीकृत प्रोजेक्ट और राशि

राज्य	अनुमोदित परियोजनाएं	लागत राशि (करोड़ रुपये में)
बिहार	39	8,427
छत्तीसगढ	50	3,007
दिल्ली	40	5,146
हरियाणा	77	3,823
हिमाचल प्रदेश	19	309
जम्मू-कश्मीर	68	994
झारखंड	18	4,066
मध्य प्रदेश	333	12,309
पंजाब	164	3,521
उत्तर प्रदेश	442	26,263
उत्तराखंड	27	711
बंगाल	211	9,792

दैनिक जागरण

हर बूंद हो स्वच्छ
हर घूंट हो स्वस्थ

स्थानीय निकायों में बड़े बदलाव की जरूरत

नगर निगमों को गंभीर वित्तीय और शासन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वे राज्य और केंद्र सरकार की ग्रांट पर बहुत अधिक निर्भर हैं। सीमित राजस्व, कर्मचारियों की कमी और चुनाव में देरी के कारण, वे बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने में संघर्ष कर रहे हैं। स्थानीय सरकारों को मजबूत बनाने और सर्विस डिलीवरी में सुधार के लिए एक बड़े बदलाव की जरूरत है।

शहरों की रीढ़ हैं नगर निगम

देश के बड़े शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) अपने 25 प्रतिशत वित्तीय संसाधनों के लिए राज्य और केंद्र सरकार पर निर्भर हैं। नगर निगम भारत में शहरी शासन की रीढ़ हैं, जिन्हें पानी की सप्लाई, कचरा प्रबंधन और बुनियादी संरचनाओं के विकास जैसी जरूरी सेवाओं का प्रबंधन करने का काम सौंपा गया है। उनकी वित्तीय स्थिति नाजुक है।

25% वित्तीय संसाधनों के लिए राज्य और केंद्र सरकार पर निर्भर हैं बड़े शहरी स्थानीय निकाय

प्रशासन की चुनौतियां

स्रोत: आरबीआई की रिपोर्ट, 2024

1400 शहरों या कस्बों में नहीं थे चुने हुए मेयर 2023 में

61% केंद्र शासित प्रदेशों में देरी से हुए हैं चुनाव

45% मतदान रहा है स्थानीय निकायों चुनावों में

41% पद खाली है देश के नगर निगमों में

58% पद खाली हैं देश की नगर पंचायतों में

35% तक कर्मचारियों की कमी है स्थानीय निकायों में

सीमित उधारी क्षमता

0.05% प्रतिशत ही है नगर निगमों की उधारी क्षमता

5.2% है कुल प्राप्तियों में वित्तीय संस्थानों से उधारी की हिस्सेदारी

- कुछ सौ करोड़ रुपये ही जुटा पाते हैं म्यूनिसिपल बांड हर साल
- जरूरी प्रोजेक्ट और इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए संसाधन जुटाने में समस्याएं
- इनोवेटिव वित्तीय विकल्प तलाशने की जरूरत

नगर निगमों से राजस्व आय बहुत कम

0.6% जीडीपी का ही राजस्व आय हो पा रही है देश के 232 नगर निगमों से

30% से भी कम है भारत के नगर निगमों का अपना राजस्व कुल खर्च का

18 अरब डालर था 232 नगर निगमों का पूंजीगत खर्च 2023 में

0.12% ही है प्रापर्टी टैक्स से मिलने वाला राजस्व भारत की जीडीपी का

11.4% है प्रापर्टी टैक्स की हिस्सेदारी अमेरिका के कुल राजस्व में

55 अरब डालर सालाना निवेश की जरूरत है इन्फ्रास्ट्रक्चर जरूरतों के लिए भारत में

जल-सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर देश

वर्तमान समय में जल सबसे कीमती संसाधनों में से एक बन गया है। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के कारण एक बड़ी आबादी पानी की किल्लत का सामना कर रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए देश में जल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आम बजट 2025-26 में बड़ी राशि आवंटित की गई है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में पेय जल पहुंचाने का काम तेजी से हो रहा है। उम्मीद है कि 2026 में पानी के संकट का सामना कर रहे परिवारों को आसानी से पेयजल उपलब्ध होगा।

₹67,000 करोड़ विशेष रूप से जल जीवन मिशन के लिए निर्धारित किए गए हैं

₹74,226 करोड़ की राशि आवंटित की गई है केंद्रीय बजट 2025-26 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए

5.2 लाख जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के साथ तेलंगाना जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) 1.0 पहल के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है

4.05 लाख पूर्ण परियोजनाओं के साथ दूसरे स्थान पर रहा छत्तीसगढ़

3.64 लाख जल संरक्षण संरचनाओं के साथ राजस्थान रहा तीसरे स्थान पर

जल की सबसे अधिक खपत कृषि क्षेत्र क्षेत्र में

उन्नत तकनीक से जल प्रबंधन

केंद्र सरकार जल प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए उन्नत तकनीकों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रही है। शहरी और ग्रामीण जल प्रणालियों के परिवर्तन के लिए सरकार प्रौद्योगिकी-आधारित दक्षता पर जोर दे रही है। जल उपयोग की निगरानी, रिसाव का पता लगाने और वितरण में सुधार के लिए एआइ, आइओटी और डिजिटल मैपिंग का उपयोग जल संसाधनों के प्रबंधन और आवंटन में महत्वपूर्ण सुधार लाएगा। इन नवाचारों से भारत के लिए अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ जल भविष्य की नींव रखी जाएगी। आइओटी-सक्षम जल निगरानी प्रणालियों, एआइ-संचालित विश्लेषण और डिजिटल मैपिंग उपकरणों के एकीकरण से जल वितरण की वास्तविक समय में निगरानी, रिसाव का पता लगाना और गुणवत्ता नियंत्रण संभव हो सकेगा।

ये योजनाएं कर रहीं हैं जल-सुरक्षित भविष्य का निर्माण

अमृत 2.0

500 अमृत शहरों में पूर्ण सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन व्यवस्था लागू करके शहरों को आत्मनिर्भर और जल-सुरक्षित बनाना है पहल का उद्देश्य

1,14,220.62 करोड़ की कुल 3,568 जल आपूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है इस मिशन के तहत

181 लाख नए नल कनेक्शन भी स्वीकृत किए गए हैं

अटल भूजल योजना

8,203 जल-संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों में संचालित है 2019 में शुरू की गई अटल भूजल योजना

81,000 जल आपूर्ति के लिए संरचनाओं का निर्माण या नवीनीकरण

9 लाख हेक्टेयर भूमि को कुशल जल उपयोग प्रथाओं के अंतर्गत लाया गया है इस योजना के तहत, जल संरक्षण और भूजल रीचार्ज के लिए

जल जीवन मिशन

12.50 करोड़ घरों को नए जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिससे यह देश में सबसे तेजी से विकसित हो रहे ग्रामीण अवसंरचना मिशनों में से एक बन गया है। यह मिशन भूजल पुनर्भरण, अपशिष्ट जल प्रबंधन, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देता है।

नए साल में नई उड़ान भरने को तैयार अर्थव्यवस्था

यहां स्कैन करें

आलोक जोशी | वरिष्ठ पत्रकार

नया साल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ समाचार लेकर आया है और साथ ही बड़ी चुनौती भी। 2025 के खत्म होते-होते सरकार ने एलान किया कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यही नहीं, अगले ढाई-तीन साल में जर्मनी को पछाड़कर यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हालांकि, इन आंकड़ों की औपचारिक पुष्टि इस वर्ष ही होगी, जब दुनिया भर की जीडीपी के आधिकारिक आंकड़े जारी होंगे। सरकारी बयान के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार अब 4.18 लाख करोड़ डॉलर का हो गया है और उसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। अनुमान है कि साल 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 7.3 लाख करोड़ डॉलर या ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा।

आईएमएफ के आकलन में भारत की अर्थव्यवस्था 2026 में 4.51 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने जा रही है, जबकि जापान के लिए यह आंकड़ा 4.46 ट्रिलियन डॉलर रहेगा। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है कि आप लाइन में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। यह पिछले कुछ सालों की भारत की तेज तरक्की और घरेलू मांग में मजबूती का नतीजा है। बीते वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी में 8.2 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई, जो पिछली छह तिमाही में सबसे तेज रफ्तार थी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि 2025-26 में भारत की वास्तविक विकास दर या रियल रेट ऑफ ग्रोथ 6.2 से 6.5 प्रतिशत के बीच रह सकती है। यह शेष दुनिया के औसत से काफी ऊपर है। इस चुनौतीपूर्ण समय में भी भारतीय अर्थव्यवस्था अपने बराबर या बड़े देशों के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 4.18 ट्रिलियन डॉलर का हो गया है और साल 2030 तक इसके 7.3 ट्रिलियन के होने का अनुमान है।

सवाल यह है कि तरक्की की यह रफ्तार क्या यूं ही जारी रहेगी? हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जीडीपी के विशाल आकार के सामने भारत की जनसंख्या भी विकराल हो चुकी है। आकार में भारतीय अर्थव्यवस्था भले आगे बढ़ गई हो, पर जब इसे प्रति-व्यक्ति आय या प्रति-व्यक्ति जीडीपी जैसे पैमाने पर कसा जाता है, तब हम जापान के मुकाबले बहुत पीछे हो जाते हैं।

लगभग तीन दशक बाद जापान में ब्याज दरें फिर से बढ़नी शुरू हुई हैं और दुनिया से पूंजी का प्रवाह फिर जापान की तरफ हो रहा है। ऐसे में, यह मानकर बैठ जाना गफलत होगी कि जापान रेस में पीछे छूट गया है और आगे मैदान साफ है। हां! जर्मनी और जापान को अलग रखकर भारत की तस्वीर देखें, तो यह साफ है कि पिछले कुछ साल, बल्कि दशकों में भारत की तरक्की के पीछे क्या-क्या कारक रहे हैं- युवा आबादी, लगातार फैलता मध्यवर्ग, अर्थव्यवस्था का तेज डिजिटलीकरण और निर्यात में मजबूती, खासकर सेवाओं का निर्यात इसमें बड़ी भूमिका निभाता रहा है। अब यहां से आगे आर्थिक व औद्योगिक विकास की रफ्तार इस बात से तय होनी है कि बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना निवेश होता है व औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धा एवं अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में बेहतर बनने के लिए क्या-क्या किया जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को परेशानी में डालने वाले इस समय दो बड़े कारण मौजूद हैं- अमेरिकी टैरिफ और डॉलर के मुकाबले कमजोर रुपया। अमेरिकी डॉलर 91 रुपये के पार जा चुका है और 89-90 के बीच झूल रहा है। पिछले कई सालों में यह रुपये का सबसे कमजोर स्तर है। इसके कई कारण सामने हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक या एफपीआई पिछले लगभग पूरे साल जबर्दस्त बिकवाली करते रहे। अनुमान है कि साल भर में उन्होंने भारत के बाजार से करीब 18 अरब डॉलर की रकम निकाली है। इसने भी रुपये पर दबाव बनाया व डॉलर की मांग बढ़ने के साथ व्यापार के मोर्चे पर भी माहौल काफी अनिश्चित हो गया है। अमेरिकी टैरिफ की वजह से न सिर्फ निर्यात कारोबार पर असर पड़ा है, बल्कि कंपनियों के लिए भविष्य की योजना बनाना भी मुश्किल हो गया है।

कहा जा सकता है कि आकार के मामले में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी बड़ा बनता जा रहा है, पर उसके सामने काफी बड़े जोखिम और चुनौतियां भी मौजूद हैं। इनको समझना और इनके बीच सबका साथ सबका विकास का रास्ता निकालना ही आगे की राह को हमवार करेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)